



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

वर्ष 2021-2022 के लिए जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)
की अनुदानों की पूरक मांगों तथा वर्ष 2022-2023 का बजट

निर्मला सीतारामन
वित्त मंत्री
का
भाषण

**Supplementary Demands for Grants of the Union Territory of Jammu & Kashmir
(With Legislature) for 2021-2022 and Budget for 2022-2023**

**SPEECH
OF
NIRMALA SITHARAMAN**
MINISTER OF FINANCE

मार्च / March 14, 2022

2021-22 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल के साथ) हेतु
अनुदान की पूरक मांगों और 2022-23 के लिए बजट

निर्मला सीतारामन

वित्त मंत्री

का भाषण

अध्यक्ष महोदय,

1. इस सम्मानित सदन में माननीय सदस्य जानते हैं कि "जम्मू-कश्मीर पुनर्संगठन अधिनियम, 2019" जो दिनांक 31.10.2019 से प्रभावी है, के अनुसार, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र राजपत्र अधिसूचना एसओ 3937 (ई) दिनांक 31.10.2019 के तहत राष्ट्रपति शासन के अधीन है। जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद के अधिकार के द्वारा या उसके तहत किया जाता है।
2. अगस्त, 2019 में ऐतिहासिक परिवर्तनकारी बदलावों के बाद, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और अन्य राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के बीच नवीनतम सफलता की कहानी और देश के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास का मॉडल बनने की ओर अग्रसर है। एक राष्ट्र, एक संविधान और एक ध्वज की अवधारणा को जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अपनाया गया है। सभी अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण कानूनों को हटा दिया गया है। इसके अलावा "जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019" के तहत प्रदान किए गए सभी केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया है। जम्मू-कश्मीर में लोगों के सभी वर्गों के साथ निष्पक्षता और समानता का व्यवहार किया जाता है। समाज के कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में उपयुक्त आरक्षण दिया गया है। पीओजेके और छंब के विस्थापित व्यक्तियों, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों, सीमा क्षेत्रों के निवासी और कश्मीरी प्रवासी जो सदियों से पक्षपात के शिकार रहे हैं, को सभी लाभ प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रूप से सशक्त बनाया गया है।
3. अधिवास नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है और अधिवास प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। स्थानीय युवाओं को नौकरियां प्रदान की गई हैं।
4. **लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करना:**
73^{वें} और 74^{वें} संविधान संशोधन अधिनियम के सफल क्रियान्वयन और पंचायत /शहरी स्थानीय निकायों, जिला विकास परिषद और ब्लॉक विकास परिषद चुनावों के आयोजन के बाद, सरकार का मुख्य ध्यान इन स्थानीय निकाय संस्थानों को 3एफ (निधि, कार्य और कार्यवाहक) के साथ सशक्त बनाना है। सरकार 4290 ग्राम पंचायतों को 1000 करोड़ रुपये,

प्रत्येक जिला विकास परिषद (डीडीसी) को 10 करोड़ रुपये की दर से 20 जिला विकास परिषद (डीडीसी) को 200 करोड़, प्रत्येक ब्लॉक विकास परिषद (बीडीसी) को 25 लाख रु. की दर से 285 ब्लॉक विकास परिषद (बीडीसी) को 71.25 करोड़ रुपये और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियां शुरू करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को 313 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्रदान कर रही है। पंचायतों को 27 कार्य तथा शहरी स्थानीय निकायों को 7 विभागों के कार्य हस्तांतरित किए गए हैं। लगभग 1727.50 करोड़ रुपये मनरेगा, 14^{वें} वित्त आयोग, मध्याह्न भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत पंचायतों को अंतरित किया गया है। 1455.62 करोड़ रुपये पिछले दो वर्षों में शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित किए गए हैं। 1889 पंचायत लेखा सहायकों की भर्ती की गई है।

5. परिवर्तनकारी शासन:

- क) सरकार का उद्देश्य पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह शासन प्रदान करना है। जम्मू-कश्मीर सरकार, सरकारी कार्यक्रमों और पहलों को लोगों की जानकारी में लाने के लिए "बैंक टू विलेज", "माई टाउन माई प्राइड", "जन-अभियान" और "ब्लॉक दिवस" की अनूठी पहल पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- ख) पूरे जम्मू-कश्मीर में एक व्यापक जन संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 73 केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न संसद समितियों ने सभी जिलों में सार्वजनिक बातचीत के लिए दौरा किया और सरकारी नीतियों पर, जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया एकत्र की। पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों, व्यापार, उद्योग आदि के अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ दो महीने की अवधि में बातचीत हुई जिससे शासन में सुधार और विभिन्न विकास योजनाओं और पहलों के कार्यान्वयन की उम्मीद है।
- ग) वित्तीय विवेक, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांतों की शुरुआत ने परियोजना कार्यान्वयन में क्रांति ला दी है और वित्तीय समावेशन और सामाजिक समानता को बढ़ाया है। प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। आज एक पेपरलेस, फेसलेस प्रक्रियात्मक ढांचे के माध्यम से शासन की एक भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली स्थापित की गई है। निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना और बिना प्रशासनिक स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति के कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जाता है। प्रूफ (ऑन-साइट सुविधा का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड) ऐप के माध्यम से तस्वीरों की जियो-टैगिंग और कार्यों के भौतिक सत्यापन के बिना कोई बिल पारित नहीं किया जाता है। एक-एक पैसा अब लोगों के कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। "सशक्तिकरण" (महत्वपूर्ण पारदर्शिता के लिए किए जा रहे कार्यों और संसाधनों की निगरानी और सार्वजनिक अवलोकन को सक्षम करना)/ जनभागीदारी (janbaghidari.nic.in) एक आईटी सक्षम कार्यक्रम की मदद से, जम्मू-कश्मीर के आम नागरिकों के पास किसी भी परियोजना तथा अपने-अपने क्षेत्रों में किए जा रहे व्यय की निगरानी करने की पहुंच है।

- घ) जिला स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता का आकलन करने के लिए जिला सुशासन सूचकांक रखने वाला जम्मू-कश्मीर देश का पहला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बन गया है। इस सूचकांक से शासन की बुनियादी इकाई में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद है। प्रत्येक जिले में दूसरों में पुनरावृत्ति के लिए सर्वोत्तम पहलों की पहचान की जा रही है।
- ड) एक ऐतिहासिक पहल "आपकी ज़मीन, आपकी निगरानी" की शुरुआत की गई है जिसमें जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी 20 जिलों के जमाबंदी, गिरदावरी, म्यूटेशन और मुसावी का स्कैन डाटा आम नागरिकों को उपलब्ध कराया गया है। भू-स्वामियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए तीन भाषाओं में भूमि पासबुक जारी की गई हैं।

6. कोविड प्रबंधन:

कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में जम्मू-कश्मीर पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है। पात्र आबादी के 100% टीकाकरण के साथ, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र ने 20 मिलियन वैक्सीन खुराक का आंकड़ा पार कर लिया है। 15-17 आयु वर्ग के संबंध में पूरे संघ राज्य क्षेत्र में टीकाकरण शुरू कर दिया गया है और जल्द ही 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

90300 लीटर प्रति मिनट (एलपीएम) क्षमता वृद्धि के साथ ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों में 87 की वृद्धि हुई है। डीआरडीओ द्वारा जम्मू-श्रीनगर में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 500 बिस्तरों वाले दो अस्पताल स्थापित किए गए थे।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने उन परिवारों के लिए "सक्षम" योजना शुरू की है, जिन्होंने कोविड के कारण अपने एकमात्र कमाने वाले को खो दिया है। उक्त योजना के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों को 20,000 रुपये प्रति वर्ष और कॉलेज जाने वाले छात्रों को 40,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जीवित पति या पत्नी और परिवार के सबसे बड़े आश्रित सदस्य को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

7. रोज़गार:

पिछले डेढ़ साल में विभिन्न सरकारी विभागों में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 11000 नियुक्तियां की गई हैं, जो जम्मू-कश्मीर के इतिहास में अभूतपूर्व था। पहली बार वंचित और गरीब तबके के बच्चों ने अपने सपनों को हकीकत में बदलकर योग्यता के आधार पर नौकरी हासिल की है। इसके अलावा, विभिन्न स्तरों पर 20,323 अतिरिक्त पदों की पहचान की गई है और उन्हें भर्ती के लिए जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड को भेजा गया है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर बैंक में विभिन्न स्तरों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से

1850 नियुक्तियां की गई हैं। विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत 1,37,870 युवाओं को उनके उद्यमशीलता उपक्रमों में सहायता प्रदान की गई है।

8. तेजी से विकास:

- (क) प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेज कर दी गई है। 36112 करोड़ रुपये तक का व्यय किया गया है। 25 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं / काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं और 4 अन्य परियोजनाएं चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरी होने की संभावना है।
- (ख) विभिन्न क्षेत्रों/योजनाओं के तहत वर्ष 2018-19 में 9229 कार्य/परियोजनाओं को पूरा किया गया, जबकि 2019-20 में 12637 कार्य/ परियोजनाओं को पूरा किया गया। 2020-21 में 21943 कार्य/परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों/योजनाओं के तहत 25446 कार्य/परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। इससे पता चलता है कि वर्ष 2019 से कोविड-19 महामारी और अन्य बाधाओं की चुनौतियों के बावजूद अधिक से अधिक विकास कार्य पूरे हो रहे हैं।
- (ग) अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन को सूचित करता हूं कि भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़क संपर्क अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 2018 तक प्रत्येक वर्ष औसतन 1500 से 1600 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाता था, जो अब दोगुनी से अधिक 3200 किलोमीटर हो गई है। जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र हर गांव तक सड़क की अपनी महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। बेहतर सड़कों की उपलब्धता और काजीगुंड - बनिहाल सुरंग के खुलने से अब श्रीनगर और जम्मू के बीच यात्रा का समय 10 घंटे से घटाकर 5 घंटे कर दिया गया है।
- (घ) यह उम्मीद है कि अगले वर्ष तक कश्मीर रेल नेटवर्क के जरिए देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगा। जम्मू-श्रीनगर शहरों में एलिवेटेड लाइट मेट्रो रेल 2022-23 में शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना के 2026 तक पूरा होने की संभावना है। इससे श्रीनगर और जम्मू शहरों में यातायात की भीड़ कम होगी।
- (ङ) श्रीनगर और शारजाह के बीच अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा, जम्मू और श्रीनगर में दो नए हवाईअड्डा टर्मिनल शुरू होने जा रहे हैं। किसानों और व्यापारियों की सुविधा के लिए जम्मू और श्रीनगर हवाई अड्डों पर कार्गो सुविधा प्रदान की गई है।
- (च) मेगा हाईवे और सुरंग परियोजनाओं के निर्माण के माध्यम से सड़क अवसंरचना का कार्य प्रगति पर है। कई राजमार्ग परियोजनाएं वर्तमान में निष्पादन के अधीन हैं। श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम अगले 2-3 वर्षों में पूरा किया जा रहा है जिससे जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिली है।

- (छ) श्रीनगर - सोनमर्ग रोड पर जेड- मोड़ टनल का काम तेज गति से चल रहा है, जिससे पर्यटकों को सर्दियों में भी खूबसूरत स्थानों पर घूमने का मौका मिलेगा। श्रीनगर-लेह रोड पर जोजिला टनल का काम शुरू हो गया है। छह लेन वाली दिल्ली-अमृतसर कटरा एक्सप्रेस-वे के बनने से दिल्ली से माता वैष्णो देवी श्राइन तक की यात्रा का समय घटकर 6 घंटे ही रह जाएगा।
- (ज) अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर में आजादी के बाद से केवल 3500 मेगावाट बिजली उत्पन्न हुई है। हमारे प्रयासों से जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र अगले तीन वर्षों में पनबिजली उत्पादन को दोगुना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दिशा में रतले (850 मेगावाट), किरथाई-॥ (930 मेगावाट), सावलकोट (1856 मेगावाट), दुलहस्ती-चरण ॥ (258 मेगावाट) और उरी- । चरण- ॥ (240 मेगावाट) की कुल 5 मेगा पनबिजली परियोजनाएं हैं। एनएचपीसी के सहयोग से 4134 मेगावाट की क्षमता को निष्पादन के लिए लिया गया है। इन परियोजनाओं में संभावित निवेश रु. 34882 करोड़ और पूरा होने पर जम्मू-कश्मीर बिजली अधिशेष बना देगा। परियोजनाओं के निष्पादन में होने वाली देरी को समाप्त कर दिया गया है और निष्पादन की गति तेज कर दी गई है। संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से चालू जल विद्युत परियोजनाओं किरू (624 मेगावाट), कावर (540 मेगावाट) और पकलदुल (1000 मेगावाट) का विकास किया जा रहा है और 2022-23 तक इन परियोजनाओं के प्रमुख सिविल और इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।
- (झ) अगस्त, 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों, सामुदायिक केंद्रों, आश्रम शालाओं और अन्य सरकारी कार्यालयों में पाइप से जलापूर्ति की जाएगी।

9. औद्योगिक विकास:

चुनौतियों के बावजूद, जम्मू-कश्मीर को औद्योगिक निवेश और अवसरों के लिए प्राथमिक गंतव्य स्थान में बदलने के प्रयास चल रहे हैं। नई औद्योगिक योजना के कार्यान्वयन के बाद, माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में, 47441 करोड़ रुपये के 4226 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो समय बीतने के साथ और बढ़ सकते हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन नीति जो क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए एक प्रमुख बाधा थी, को सरल बनाया गया है जिससे अधिक निवेश आकर्षित होने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर ने हाल ही में दिसंबर 2021 में पहली बार ऐतिहासिक रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें 18,300 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसी तरह दुबई एक्सपो में जम्मू-कश्मीर एक प्रमुख आकर्षण रहा जिसे जनवरी, 2022 में आयोजित किया गया। वैश्विक निवेशकों ने जम्मू-कश्मीर में निवेश करने और रुपये के निवेश प्रस्तावों के लिए गहरी दिलचस्पी दिखाई। 3000 करोड़ रुपये के निवेश को अंतिम रूप दिया गया। कारोबारी सुगमता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और सभी आवश्यक सेवाओं को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है।

10. कोविड -19 महामारी के पश्चात आर्थिक सुधार:

- क) कोविड प्रबंधन के लिए किए गए व्यापक उपायों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2021-22 की शुरुआत तेजी से आर्थिक सुधार की प्रबल आशा के साथ हुई हालांकि तीसरी लहर का डर बना हुआ था, जिससे आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने का खतरा था। जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था ने अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में 2020-21 के दौरान तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। 2021-22 के दौरान अर्थव्यवस्था के मौजूदा कीमतों पर 7.5% बढ़ने की उम्मीद है।
- ख) एसजीएसटी संग्रह फरवरी, 2022 तक 1897 करोड़ रुपये रहा है, जो फरवरी, 2021 तक 1389 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष (2021) की इसी अवधि की तुलना में 36.57% अधिक है। फरवरी, 2021 तक 2921 करोड़ रुपये के मुकाबले फरवरी, 2022 तक आईजीएसटी समझौता 3917 करोड़ रुपये रहा है, जिसमें पिछले वर्ष (2021) की इसी अवधि में 34.09% की वृद्धि दर्ज की गई है। फरवरी, 2022 तक स्टाम्प संग्रह 398 करोड़ रुपये रहा है, जो फरवरी, 2021 तक 236 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष (2021) की इसी अवधि की तुलना में 68.64 प्रतिशत अधिक है। एमएसटी अधिनियम के तहत फरवरी, 2022 को समाप्त होने तक पेट्रोल और डीजल की बिक्री से राजस्व की वसूली पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए 31.51% की वृद्धि दर्ज करते हुए 1320 करोड़ रु की तुलना में फरवरी, 2021 में 1736 करोड़ रु. हुई। आबकारी संग्रह फरवरी, 2022 तक 1444 करोड़ रुपये रहा है, जो फरवरी, 2021 तक 1186 करोड़ रुपये था जो इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष (2021) की तुलना में 21.75% की वृद्धि दर्ज करते हुए 258 करोड़ रुपये अधिक है। संक्षेप में कहें तो, कर संग्रह महत्वपूर्ण वृद्धि और लचीलापन दिखा रहा है जो इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तेजी से आर्थिक सुधार की राह पर है।
- ग) पर्यटन क्षेत्र में भी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। दिसंबर, 2021 में लगभग 1.43 लाख पर्यटकों ने कश्मीर का दौरा किया जो पिछले 7 वर्षों में सबसे अधिक है। सितंबर 2021 से तीर्थयात्रियों सहित लगभग 72.09 लाख पर्यटकों ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया जो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अधिक है। सर्दियों के मौसम में श्रीनगर और प्रमुख पर्यटन स्थलों विशेष रूप से गुलमर्ग और पहलगाम में 100% हाई-एंड-होटल ऑक्यूपेंसी देखी गई है।
- घ) सूखे और ताजे फलों का निर्यात बढ़ रहा है और जनवरी, 2022 के अंत तक लगभग 17.09 लाख मीट्रिक टन निर्यात किया जा चुका है।

11. वित्तीय समावेशन:

- क) अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर सरकार ने कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने के लिए सुनियोजित कदम उठाए हैं। सितंबर, 2020 में घोषित 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है और अब तक उक्त पैकेज के अन्य उपायों के कार्यान्वयन के अलावा, 3.44 लाख खाताधारकों /

उधारकर्ताओं के मामले में 6 महीने के लिए 5% ब्याज आर्थिक सहायता के रूप में 750 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

- ख) आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन -1 (जीईसीएल-1) के तहत 60736 उधारकर्ता लाभान्वित हुए हैं जिसमें 1878 करोड़ रुपये शामिल हैं, 98566 व्यक्तिगत लाभार्थियों को मुफ्त चावल और 31069 परिवारों को दालें प्रदान की गईं। 74.37 करोड़ रुपये के व्यापार सहायता ऋण के तहत 289 उधारकर्ताओं को लाभान्वित किया गया है। पीएम-स्वनिधि योजना के तहत 14514 लाभार्थियों को 10000 रुपये की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी के साथ पथ विक्रेताओं के लिए विशेष ऋण सुविधा वितरित की गई है। 8.27 लाख केसीसी (फसल) खाताधारकों को 5841 करोड़ रुपये और 1.26 लाख केसीसी-पशुपालन और मत्स्य पालन (एएच एंड एफ) खाताधारकों को 637 करोड़ का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 3464 करोड़ रु. का ऋण 1,52,703 लाभार्थियों को वितरित किया गया है।
- ग) जबकि 23,434 ऋण मामले जिसमें “बैंक टू विलेज” कार्यक्रम के दौरान चिन्हित किए गए युवाओं के लिए 407 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, 19,645 युवाओं को पहले ही अपने स्वयं के व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से 336.79 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जा चुका है जिसमें 6679 महिला उद्यमी शामिल हैं।

12. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार का इरादा व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं, विशेष रूप से विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 100% कवरेज हासिल करने का है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 100% आधार सीडिंग के अलावा सभी लाभार्थी योजनाओं के संबंध में 100% परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस वर्ष विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 65 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2017 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक सुरक्षा के लाभों का विस्तार करने के लिए 272465 लाभार्थियों को जोड़ा गया है। 1.66 लाख से अधिक श्रमिकों को चार महीने के लिए 1000 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की गई है। 70,000 से अधिक निराश्रितों, कच्ची बस्ती में रहने वालों, प्रवासी मजदूरों को राशन उपलब्ध कराया गया।

13. बजट 2022-23:

13.1 जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए बजट 2022-23 में सुशासन, गहनता, जमीनी लोकतंत्र, त्वरित विकास और समावेशी विकास, निवेश और औद्योगिक विकास की सुविधा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अवसंरचना विकास, और रोजगार, युवा पहल और महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेश का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

13.2 जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए 2022-23 का बजट फिर से 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगा, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को विकास का एक मॉडल बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का सूचक है। 1,42,150 करोड़ रुपये (29,200 करोड़ रुपये के अर्थोपाय अग्रिम सहित) के सकल बजट में से कुल बजट अनुमान 1,12,950 करोड़ रुपये (निवल) है, जिसमें से विकासात्मक व्यय 41,335 करोड़ रुपये है।

13.3. बजट के पूंजी घटक में काफी वृद्धि हुई है। अपेक्षित राजस्व प्राप्तियां 1,02,322 करोड़ रुपये हैं जबकि राजस्व व्यय 71,615 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है जिससे पूंजीगत व्यय के लिए 30,707 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष उपलब्ध होगा।

13.4. पूंजीगत प्राप्तियां 10,628 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 41,335 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। निर्धारित बजट का 37% विकास और अवसंरचना परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा।

14 सामाजिक-आर्थिक विकास:

14.1 कृषि, बागवानी और रेशम उत्पादन क्षेत्र:

- (क) सरकार का लक्ष्य उच्च उपज/उच्च घनत्व वाली फसलों की खेती, आधुनिक तकनीक और प्रयोगशाला परीक्षण कीटनाशकों और अन्य उपायों के उपयोग को प्रोत्साहित करके किसान की आय को दोगुना करना है।
- (ख) 15240 हेक्टेयर क्षेत्र में 55.80 करोड़ रु के प्रावधान सहित 3200 पंप सेट, 898 बोरवेल, 10000 ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर 16960 किसान लाभान्वित होंगे।
- (ग) 23.97 करोड़ रुपये का निवेश सहित 8.93 लाख किसान उच्च उपज वाली किस्मों/हाइब्रिड बीज के वितरण से लाभान्वित होंगे।
- (घ) 27 करोड़ रुपये के प्रावधान सहित 36000 किसानों को क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- (ङ) 81.00 करोड़ रुपये के प्रावधान सहित 33200 किसानों को कृषि मशीनरी उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जाएगा।
- (च) 44204 किसानों को 2 करोड़ सब्जी की पौध उपलब्ध कराकर और आलू के तहत 45 हेक्टेयर का विस्तार, जैविक खेती के तहत 756 हेक्टेयर और मसालों के तहत 250 हेक्टेयर के विस्तार सहित 6.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से लाभान्वित किया जाएगा।
- (छ) 1.60 करोड़ रु के प्रावधान सहित 11 बड़ी/छोटी मंडियों की स्थापना से 22000 किसान लाभान्वित होंगे।

- (ज) 8670 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई फील्ड चैनलों के रखरखाव द्वारा बहाल की जाएगी जिसके लिए 30.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- (झ) 80 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन के माध्यम से 12800 किसानों को शामिल किया जाएगा।
- (ञ) जबकि लगभग 1.70 लाख मीट्रिक टन की नियंत्रित वातावरण भंडारण क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है, वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक और 30,000 मीट्रिक टन जोड़े जाने की संभावना है। वर्ष 2022-23 के दौरान 50,000 मीट्रिक टन नियंत्रित वातावरण भंडारण क्षमता को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले तीन वर्षों में लगभग 5 लाख मीट्रिक टन की नियंत्रित वातावरण क्षमता प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- (ट) जम्मू-कश्मीर सरकार, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (एनएएफईडी) के सहयोग से अगले पांच वर्षों में 5500 हेक्टेयर क्षेत्र में उच्च घनत्व वृक्षारोपण कर रही है। तदनुसार मार्च, 2021 में उच्च घनत्व वृक्षारोपण से संबंधित एक नई योजना शुरू की गई जिसमें सेब के अलावा जम्मू और कश्मीर में उगाई जाने वाली अन्य फसलें भी शामिल हैं। वर्ष 2022-23 में सेब के लिए उच्च घनत्व वृक्षारोपण के अंतर्गत 400 हेक्टेयर और उपोष्णकटिबंधीय फलों के लिए 1000 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल करने का लक्ष्य है।
- (ठ) चकरोही जम्मू में 12.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 800 हेक्टेयर क्षेत्र में उपोष्णकटिबंधीय फलों के पौधों के लिए सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत मेगा उच्च घनत्व वृक्षारोपण नर्सरी स्थापित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 के दौरान निजी क्षेत्र में 10 उच्च घनत्व वृक्षारोपण नर्सरी का लक्ष्य रखा गया है।
- (ड) ओलावृष्टि से फसल में होने वाली क्षति को रोकने के लिए “परवाज़” योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से ओला रोधी निवल पर सब्सिडी का प्रस्ताव किया गया है।
- (ढ) एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) सूची के अनुसार सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन और नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- (ण) गुणवत्तायुक्त रेशमकीट बीज के उत्पादन के लिए 5 रेशमकीट बीज इकाइयों और चाकी पालन केंद्रों के लिए 1.89 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- (त) बाजार विपणन सुविधाओं के निर्माण के लिए 02 कोकून नीलामी बाजार का निर्माण/उन्नयन किया जाएगा जिसके लिए 86.13 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
- (थ) 1.00 करोड़ रुपये के प्रावधान सहित कोकून उपज को बढ़ाने के लिए कोकून पालन केंद्र की सहायता हेतु 400 किसानों को पालन-पोषण उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

वर्ष 2022-23 के लिए कृषि और बागवानी क्षेत्रों हेतु पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लगभग 1950.04 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 310.08 करोड़ रुपये अधिक है।

14.2 पशु, भेड़ पालन और मत्स्य पालन क्षेत्र:

- (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 5000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के सृजन सहित लगभग 2000 डेयरी इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- (ख) निजी उद्यमियों के लिए दूध प्रसंस्करण क्षेत्र में बल्क मिल्क कूलर, दूध प्रसंस्करण/ पनीर बनाने की मशीन, विपणन सुविधाएं जिसमें दूध एटीएम और दूध परिवहन वैन, दूध देने वाली मशीनें और डेयरी फार्म अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं, के रूप में भी समर्थन बढ़ाया जाएगा। महिला उद्यमियों और अन्य आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को शामिल करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- (ग) पशु-भैंसों से संबंधित दुग्ध उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने के लिए लगभग 13 लाख कृत्रिम वीर्यसेचन के माध्यम से किसानों के 4.60 लाख प्रजनन योग्य डेयरी गायों/भैंसों को निःशुल्क कृत्रिम वीर्यसेचन सेवा प्रदान की जाएगी।
- (घ) वर्तमान वार्षिक दुग्ध उत्पादन 2505 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 2800 हजार मीट्रिक टन होने की उम्मीद है।
- (ङ) लगभग 2400 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजन सहित लगभग 1200 भेड़/बकरी इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- (च) 8000 से अधिक कुलीन मेमनों के उत्पादन के लिए स्थानीय भेड़ों के आनुवंशिक उन्नयन के लिए 200 एलीट क्रॉस ब्रेड आयातित मेरिनो भेड़ को लाया जाएगा। इससे शवों की उपज मौजूदा 18 किलोग्राम से बढ़कर 21 किलोग्राम हो जाएगी, इसके अतिरिक्त, उन का उत्पादन मौजूदा 2 किलोग्राम से बढ़कर 2.5 किलोग्राम प्रति भेड़ हो जाएगा।

- (छ) पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन सेवाओं की घर पर वितरण सेवाएं प्रदान करने के लिए 44 मोबाइल पशु चिकित्सालयों को संचालित करने का प्रस्ताव है। विभिन्न अनुसूचित पशु रोगों के लिए लगभग 78 लाख पशुधन और 5 करोड़ कुक्कुट पक्षियों का टीकाकरण किया जाएगा।
- (ज) एकीकृत कुक्कुट विकास योजना के अंतर्गत, कुक्कुट पक्षियों का बीमा, कुक्कुट फर्म के लिए उपकरण /मशीनरी, कुक्कुट प्रसंस्करण उपकरण, प्रतिपादक इकाइयां तथा कुक्कुट परिवहन वाहनों की खरीद के साथ-साथ नया कुक्कुट फार्म शुरू करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देकर स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- (झ) वर्ष 2022-23 के दौरान 35000 बैकयार्ड पोल्ट्री इकाइयां स्थापित किया जाने का अनुमान है।
- (ञ) चारा प्रदर्शन भूखंडों की स्थापना, उन्नत चारा मिनी बीज किटों के वितरण, चारा मशीनीकरण और पशु चारा संयंत्रों/साइलेज संयंत्रों/चारा ब्लॉक बनाने की मशीनों और हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन की स्थापना के साथ चारे की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- (ट) संदिग्ध नमूनों के शीघ्र परीक्षण के लिए संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में एवियन इन्फ्लुएंजा परीक्षण सुविधा प्रदान की जाएगी।
- (ठ) वर्ष 2022-23 के दौरान ट्राउट उत्पादन को 1400 मीट्रिक टन से 2800 मीट्रिक टन तक दोगुना करने के साथ-साथ मत्स्य उत्पादन को वर्तमान के 24,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 33,000 मीट्रिक टन किए जाने की उम्मीद है।
- (ड) बायोफ्लोक और री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जैसी नवीनतम तकनीकी हस्तक्षेपों के आधार पर गहन मत्स्य पालन इकाइयों की स्थापना पर जोर दिया जाएगा।
- (ढ) पूरे देश और विदेश के उपभोक्ताओं के लिए ट्राउट को सुलभ बनाने के लिए, संपूर्ण जम्मू-कश्मीर में मत्स्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे मत्स्य किसानों के उत्पादन और पारिश्रमिक को बढ़ावा मिलेगा।
- (ण) "परवाज़" योजना के तहत, विभिन्न शहरों और मध्य पूर्व के देशों में ट्राउट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रियायती हवाई माल भाड़ा सुविधा प्रदान की जाएगी।
- (त) ट्राउट की ब्रांडिंग और इसके निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर देने सहित जन जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा।

वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय के अंतर्गत पशु, भेड़ पालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए लगभग 391.90 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 38.86 करोड़ रुपये अधिक है।

14.3 स्वास्थ्य और कल्याण:

- (क) प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5.00 लाख रुपये तक मुफ्त बीमा कवर प्रदान करने के लिए आयुषमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अभिसरण में व्यापक स्वास्थ्य कवरेज योजना सुचारू रूप से प्रगति कर रहा है। 55.56 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। एबी-पीएमजेएवाई के तहत स्वीकृत 1,592 चिकित्सा पैकेज जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य योजना (सेहत) के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस बीमा कवर के तहत जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों को शामिल करने के उद्देश्य से वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान शामिलकरण की गति को तेज किया जाएगा।
- (ख) शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को एकल अंक में लाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) बजट के तहत आवश्यक प्रावधान निर्धारित किया गया है।
- (ग) जम्मू-कश्मीर सरकार का इरादा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान हंदवाड़ा (कुपवाड़ा) और उधमपुर के दोनों नए चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस कक्षाओं का पहला बैच शुरू करना है, जिससे जम्मू-कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र में कुल प्रवेश क्षमता 1300 एमबीबीएस सीटों तक बढ़ जाएगा।
- (घ) बेहतर रोगी प्रबंधन और रेफरल में कमी के लिए नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी।
- (ङ) शेष सभी 07 नर्सिंग कॉलेजों को वर्ष 2022-23 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2022-23 के पूंजीगत व्यय के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 1484.72 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

14.4 ग्रामीण अर्थव्यवस्था:

- (क) मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान 426 लाख कार्यदिवस सृजित करने का लक्ष्य है। मांग के आधार पर 60,000 जॉब कार्ड जारी करने का प्रस्ताव है और विभिन्न प्रकृति के 1 लाख विकास कार्य शुरू किए जाने और पूरा होने की उम्मीद है।

- (ख) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत, 1500 निर्वाचित प्रतिनिधियों को संघ राज्य क्षेत्र के बाहर प्रदर्शन दौरा कराया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से 1,12,000 प्रतिभागियों (पीआरआई/संबंधित विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों) को क्षमता निर्माण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर के संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। 400 नई और 300 मौजूदा पंचायत घरों में क्रमशः निर्माण और नवीनीकरण संबंधी कार्य किया जाएगा।
- (ग) वर्ष 2022-23 के दौरान पीएमएवाई (जी) के अंतर्गत 54,000 घरों का निर्माण किया जाएगा।
- (घ) स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम (जी) के तहत 2022-23 के दौरान 87,250 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और 2,500 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
- (ङ) एनआरएलएम के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान 21,194 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन करने का प्रस्ताव है, 20,000 परिक्रामी निधि और 18,000 बैंक लिंकेज को शामिल करने का लक्ष्य है।
- (च) हिमायत दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान 14,067 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और 9,847 नौकरियां दिए जाने का प्रस्ताव है।
- (छ) जिला विकास परिषद/ब्लॉक विकास परिषद/पंचायती राज संस्था (डीडीसी/बीडीसी/पीआरआई) के सदस्यों के लिए आवासीय/कार्यालय आवास का निर्माण शुरू कर दिया गया है। 2022-23 के लिए 176.32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23 के पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लगभग 4627.85 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 327.40 करोड़ रुपये अधिक है।

14.5 विद्युत क्षेत्र:

- (क) सरकार जम्मू-कश्मीर को अतिरिक्त बिजली बनाने, सभी आपूर्ति बाधाओं को दूर करने और 24X7 गुणवत्ता वाली बिजली प्रदान करने की दृष्टि से बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- (ख) पिछले 2 वर्षों में परिवर्तन क्षमता में 150% की वृद्धि हुई है। ट्रांसमिशन सेक्टर के अंतर्गत मौजूदा क्षमता को बढ़ाने और नए ग्रिड सब-स्टेशनों के निर्माण/मौजूदा ग्रिड सब-स्टेशनों में तीव्रता लाकर और मौजूदा एसीएसआर (एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित) केबल्स को

एचटीएलएस (उच्च तापमान कम शिथिलता) कंडक्टर द्वारा बदलने के माध्यम से महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन लाइनों की वहन क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- (ग) मार्च, 2022 तक ट्रांसमिशन क्षमता 12655 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है और 2022-23 में 220/132 किलोवाट स्तर और 132/33 किलोवाट स्तर पर ट्रांसमिशन क्षमता क्रमशः 520 एमवीए और 580 एमवीए बढ़ने की उम्मीद है।
- (घ) ग्राउंड क्लियरेंस के लिए विभिन्न स्थानों पर टावरों की स्थापना के अलावा मौजूदा एसीएसआर के लगभग 160 सर्किट किलोमीटर को एचटीएलएस कंडक्टर द्वारा 1.75 गुना बढ़ाने के लिए प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
- (ङ) पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) एक नया सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी योजना है जो विद्युत मंत्रालय (जीओआई) द्वारा शुरू की गई है , जिसका उद्देश्य कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) घाटे में कमी, 100% प्री-पेड मीटरिंग, सेवा की औसत लागत में कमी- कुल राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर), आधुनिक डिस्कॉम विकसित करना और संचालन क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाया जाएगा और 2022-23 के दौरान इसे जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में चालू किया जाएगा।
- (च) 11/0.33 किलोवाट महत्वपूर्ण रूप से ओवरलोड वाले सब-स्टेशनों के निर्माण/उनमें तेजी लाकर एचटी/एलटी लाइनों में सुधार/उनका नवीनीकरण द्वारा उपभोक्ताओं तक विश्वसनीय और गुणवत्ता परख विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी।
- (छ) बिजली चोरी के खिलाफ प्रवर्तन अभियान को और तेज किया जाएगा और घाटे को कम करने और राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के लिए इसे एक नियमित फीचर बनाया जाएगा।
- (ज) बिलिंग दक्षता और राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए आईटी और ऑनलाइन बिलिंग/संग्रह पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) के डेटाबेस को डिजिटाइज़ करने और शेष फीडरों को राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (एनपीपी) पर ऑन-बोर्ड करने की प्रक्रिया 2022-23 के दौरान पूरी की जाएगी ।
- (झ) बिलिंग/संग्रह में मानवीय हस्तक्षेप को रोकने और बाद में समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटे में कमी के लिए 6 लाख स्मार्ट प्री-पेड मीटर (जम्मू और कश्मीर डिवीजन के लिए 3 लाख प्रत्येक) स्थापित किए जाएंगे।

विद्युत क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23 के पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लगभग 2,457.58 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

14.6 पर्यटन और संस्कृति:

- (क) जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र बहु तमहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध पर्यटन के अवसरों को प्रदर्शित करते हुए जीवंत अभियान और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- (ख) जम्मू-कश्मीर में 75 ऑफ बीट गंतव्यों की पहचान की गई है। इन गंतव्यों को 75वें "आजादी का अमृत महोत्सव" के अंतर्गत पर्यटकों के लिए उचित बुनियादी ढांचे और अपेक्षित सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा।
- (ग) सार्वजनिक और निजी निवेश मॉडल के माध्यम से अनछुए पर्यटन स्थलों का पता लगाया जाएगा।
- (घ) साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देकर जल आधारित पर्यटन गतिविधियों की संभावनाओं का पूंजीकरण किया जाएगा।
- (ङ) उच्च राजस्व उत्पन्न करने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करके गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (च) सड़क किनारे विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी इसके अलावा पर्यटन से संबंधित संपत्तियों का नवीनीकरण और उन्नयन किया जाएगा ताकि उच्च तबके के पर्यटकों को और आकर्षित किया जा सके।
- (छ) जम्मू-कश्मीर के विरासत स्थलों के संरक्षण और बचाव की दिशा में एक कदम के रूप में स्थानीय त्यौहार गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा स्थानीय फिल्म/सिनेमा/थिएटर के माध्यम से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा।

पर्यटन एवं संस्कृति क्षेत्रों के लिए वर्ष 2022-23 के पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लगभग 604.77 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 78.61 करोड़ रुपये अधिक है।

14.7 जल शक्ति विभाग:

I. पीएचई क्षेत्र:

- (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100% पाइपड जलापूर्ति के उद्देश्य

को प्राप्त करने का अंतिम वर्ष है। अब तक, नल के पानी के कनेक्शन वाले परिवारों का कवरेज 56.36 प्रतिशत तक पहुंच गया है जो चालू वित्त वर्ष के अंत तक 81 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है।

- (ख) "जल जीवन मिशन हर घर जल" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) 18.35 लाख परिवारों में से 10.34 लाख परिवारों तक पहुंच गया है। शेष परिवारों (8.01 लाख) को अगस्त, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- (ग) 2022-23 के दौरान 1589 जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है।
- (घ) गुणवत्तापूर्ण जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2022-23 में 2.50 लाख जल गुणवत्ता परीक्षण करने की योजना है। इसके अलावा सभी 20 जिला जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता प्राप्त की जाएगी और 2022-23 के दौरान सभी उप-मंडल प्रयोगशालाओं को पंजीकृत किया जाएगा।

II - सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र:

- (क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (एआईबीपी-पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत चल रही 43 लघु सिंचाई योजनाओं को 2022-23 के दौरान भौतिक रूप से पूरा किया जाएगा।
- (ख) 2022-23 के दौरान 28 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।
- (ग) तवी बैराज पर 73.34 करोड़ रुपये की लागत से शेष काम 2022-23 के दौरान पूरा होने की उम्मीद है।
- (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) साइट की विजयपुर, जम्मू में सुरक्षा के लिए 27.91 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ सुरक्षा कार्य 2022-23 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- (ङ) उज्ज्वल बहु उद्देश्यीय परियोजना (यूएमपीपी) पर काम 2022-23 के दौरान शुरू होने की उम्मीद है, जिसके लिए डीपीआर को फिर से डिजाइन किया गया है।

जल शक्ति विभाग के लिए 2022-23 के पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 9289.15 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 6412.71 करोड़ रुपये अधिक है।

14.8 आवास और शहरी विकास क्षेत्र:

- (क) अमृत-1.0 के अंतर्गत, 76 परियोजनाएं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरी होने की संभावना है और शेष परियोजनाएं 2022-23 के दौरान पूरी की जाएंगी जिनमें

पंजतीर्थी जम्मू में मल्टी लेवल कार पार्किंग सुविधा का निर्माण, तवी नदी चरण II, के 05 नालों का निर्माण, रूप नगर आदि में ग्रीन स्पेस शामिल है।

- (ख) अमृत-2.0 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में छूटे हुए प्रत्येक घर को 100% सुरक्षित नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए सिटी वाटर एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों के सभी जल निकायों का चरणबद्ध तरीके से कार्याकल्प किया जाएगा।
- (ग) स्वच्छ भारत मिशन (यू) के अंतर्गत 16 यूएलबी ने (ओडीएफ+) का दर्जा हासिल कर लिया है और 25 यूएलबी का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। शेष यूएलबी 2022-23 में ओडीएफ+ का दर्जा हासिल कर लेंगे।
- (घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के शुरू होने से 2022-23 के दौरान लगभग 70% स्रोत पृथक्करण प्राप्त होने की संभावना है।
- (ङ) श्रीनगर, जम्मू और अनंतनाग के सभी अछूते क्षेत्रों को एसबीएम (यू) -2.0 के अंतर्गत 2022-23 के दौरान चरणबद्ध तरीके से सीवरेज / सेप्टेज उपचार सुविधाओं के साथ कवर किया जाएगा।
- (च) श्रीनगर और जम्मू में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की स्थापना से प्रतिदिन लगभग 850 मीट्रिक टन कचरे के वैज्ञानिक निपटान में मदद मिलेगी और ऊर्जा उत्पादन और खाद्य अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ) के उत्पादन के अलावा दोनों शहरों में कमजोर कचरा बिंदुओं को भी समाप्त किया जा सकेगा, जिससे लगभग 20 लाख लोगों को लाभ होगा।
- (छ) 76 यूएलबी में विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना 2022-23 के दौरान पूरी की जाएगी और इन यूएलबी में उत्पन्न 690 मीट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक उपचार किया जाएगा, जिससे लगभग 14 लाख की आबादी को लाभ होगा।
- (ज) स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 270 परियोजनाओं में से 95 परियोजनाओं के चालू वित्त वर्ष के अंत तक तथा 80 और परियोजनाओं के 2022-23 में पूरा होने की संभावना है। दोनों स्मार्ट शहरों में एक बार पूरी हो जाने वाली ये परियोजनाएं वाईफाई सुविधाएं, स्मार्ट स्वास्थ्य केंद्र, रिवर वेंडिंग मशीन की स्थापना, स्मार्ट क्लास रूम, टीवी चार्जिंग स्टेशन, साइकिल ट्रैक / हॉकर जोन के विकास, फ्लाइओवर आदि के नीचे पार्किंग और जगह के विकास के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी।
- (झ) 2022-23 के दौरान 1131.07 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 9 प्रमुख सीवरेज योजनाएं निष्पादित की जाएंगी और इन परियोजनाओं के 2023-24 के दौरान पूरा होने की संभावना है, जिससे 6,20,565 की आबादी लाभान्वित होगी।

- (ज) मेसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के सहयोग से 76 यूएलबी में 2.15 लाख एलईडी लाइटें बदले जाने की संभावना है और इन यूएलबी में लगभग 14 लाख लोगों को लाभ होगा।
- (ट) दीनदयाल अंत्योदय योजना (डे-एनयूएलएम) के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए 15000 लाभार्थियों को स्वरोजगार घटक के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
- (ठ) डल झील के किनारे वेस्टर्न फोरशोर रोड का निर्माण किया जाएगा। डल झील की ड्रेजिंग और सफाई के लिए और अधिक स्वदेशी झील सफाई मशीनों की खरीद की जाएगी। 2022-23 के दौरान 1.5 वर्ग कि.मी. लिली पैड क्षेत्र को साफ किया जाएगा। 2022-23 के दौरान 1.5 वर्ग कि.मी. क्षेत्र की तटरेखा पर डीवीडिंग और तलमार्जन किया जाएगा। झील के पश्चिमी किनारे के पास 60,000 वर्गमीटर के लिए अधिग्रहीत भूमि का तलमार्जन किया जाएगा और बाद में इसे जल निकायों में बदल दिया जाएगा।

वर्ष 2022-23 के लिए आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र हेतु पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लगभग 3112.88 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 230.94 करोड़ रुपये अधिक है।

14.9 शिक्षा क्षेत्र:

I- विद्यालयी शिक्षा:

- (क) सकल नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। " आओ स्कूल चलें " के अंतर्गत गहन नामांकन अभियान शुरू किया गया है।
- (ख) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत, प्रारंभिक स्तर (I-VII) पर लगभग 8.30 लाख पात्र छात्रों के पोषण स्वास्थ्य में सुधार हेतु फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा।
- (ग) मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सीबीएसई द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा।
- (घ) प्रयोगिक आधार पर जम्मू और सांबा जिलों के शहरी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में नामांकित छात्रों को गर्म पका भोजन परोसने में एनजीओ अक्षय पात्रा को शामिल किया जाएगा।
- (ङ) स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, प्रारंभिक बाल देखभाल शिक्षा प्रदान करने और संख्यात्मक तथा बुनियादी साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में 500 किंडरगार्टन स्थापित किए जाएंगे।
- (च) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 518 स्मार्ट/वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे।

- (छ) 200 व्यावसायिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी और व्यावसायिक प्रयोगशालाओं वाले 40 विद्यालय व्यावसायिक/कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए हब के रूप में कार्य करेंगे।
- (ज) लड़कियों के लिए आवासीय सुविधाओं में सुधार और शिक्षा में वांछित लैंगिक समानता लाने के लिए 37 बालिका छात्रावास भवन और 12 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) भवनों को पूरा किया जाएगा।
- (झ) 8000 मेधावी जनजातीय छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे।
- (ञ) 2022-23 में राजौरी और शोपियां जिले में आदिवासियों के लिए दो आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा।
- (ट) यूनिसेफ द्वारा विकसित 'तलाश' एप के माध्यम से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का सर्वेक्षण किया जाएगा और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
- (ठ) 100 स्कूलों (प्रति जिले 5 स्कूल) में खेल की अवसंरचना का विकास किया जाएगा।

II - उच्च शिक्षा:

- (क) 2022-23 में 07 कॉलेज भवन बनकर तैयार हो जाएंगे।
- (ख) छात्रों के कौशल विकास के लिए 2022-23 के दौरान टाटा टेक्नोलॉजीस के सहयोग से जम्मू और श्रीनगर में आविष्कार, नवाचार, ऊष्मायन और प्रशिक्षण केंद्र (सीआईआईआईटी) स्थापित किए जाएंगे।
- (ग) जम्मू-कश्मीर के सभी कॉलेजों में उच्च शिक्षा ई-गवर्नेंस प्रणाली विकसित की जाएगी।
- (घ) 59 कॉलेजों की एनएएसी प्रत्यायन पूरी हो जाएगी।
- (ङ) 2022-23 में उच्च स्तरीय अनुसंधान और नवाचार के लिए छात्रों और शिक्षकों को अवसर प्रदान करने के लिए दो उच्च स्तरीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
- (च) 2022-23 के दौरान लगभग 20000 पूर्व-स्नातक छात्रों को कौशल वृद्धि प्रशिक्षण के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

वर्ष 2022-23 के लिए विद्यालय एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र हेतु पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लगभग 1806.66 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 249.17 करोड़ रुपये अधिक है।

14.10 सड़क संयोजकता (सड़कें और पुल):

- (क) 2022-23 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई/शहरों और कस्बों/केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना (सीआरआईएफ) (नाबार्ड) गड्डे मुक्त सड़कों

के अंतर्गत कुल मिलाकर 6000 किलोमीटर सड़कों की ब्लैक-टॉपिंग प्राप्त करने की संभावना है।

- (ख) 2022-23 के दौरान नाबार्ड के वित्त पोषण से स्वीकृत की जाने वाली 2237 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 543 नई परियोजनाओं को निष्पादन के लिए लिया जाएगा।
- (ग) सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क अनुरक्षण नीति 2021 के अनुसार 2022-23 के दौरान मौजूदा सड़क अवसंरचना के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- (घ) सरकार ने पीडब्लू (आर एंड बी) विभाग में तृतीय पक्ष निरीक्षण तंत्र प्रारंभ किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से चल रहे सभी कार्यों को तृतीय पक्ष निरीक्षण तंत्र के दायरे में लाया जाएगा।
- (ङ) 2022-23 के दौरान पीएमजीएसवाई-III की मंजूरी मिलने के बाद 1750 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन किए जाने की संभावना है।
- (च) 2022-23 के दौरान केंद्रीय/संघ शासित क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत 50 पुलों का निर्माण किया जाएगा।

वर्ष 2022-23 के लिए सड़क और पुल क्षेत्र हेतु पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लगभग 5217.87 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

14.11 उद्योग और वाणिज्य:

- (क) जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30 का फोकस नए निवेश को आकर्षित करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, पिछड़े क्षेत्रों का विकास और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों का पोषण करना है। जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30 के अनुसार संभावित उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
- (ख) सरकार संघ राज्य क्षेत्र में उद्यम प्रारंभ करने के लिए निवेशकों को सक्षम बनाने हेतु वातावरण प्रदान कर रही है, इज ऑफ ड्रिग बिजनेस (ईओडीबी) में नई प्रगति कर रही है।
- (ग) 2022-23 के दौरान घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय रोड शो सहित जम्मू-कश्मीर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- (घ) वर्ष 2022-23 के दौरान संघ शासित क्षेत्रों में नई औद्योगिक संपदाओं के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जम्मू संभाग में बुद्धि कठुआ, मीरठ घाटी, राख रारा स्वंधा मोड़ सांबा और कतली डैनी (सांबा) और कश्मीर संभाग में खोनमोह, सेम्पोरा, चंदगाम तहब, हरदू डहरुणा दूरू और हसन नूर में नवीन औद्योगिक संपदा के विकास के लिए 42.60 करोड़ रुपये उद्दिष्ट किए गए हैं।

- (ड) मौजूदा औद्योगिक संपदाओं में 7 कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान (सीईटीपी) के निर्माण के लिए रु. 3.91 करोड़ उद्दिष्ट किए गए हैं।
- (च) वर्ष 2022-23 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 1354 इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिसमें 8124 व्यक्तियों को रोजगार के साथ 25 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी शामिल है।
- (छ) 2000 सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा जिससे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से 20000 व्यक्तियों को लाभ होगा। कारीगर क्रेडिट कार्ड (एसीसी) योजना के अंतर्गत कारीगरों द्वारा 2 लाख रु . तक ऋण लेने के लिए 7% ब्याज की सरकारी आर्थिक सहायता उपलब्ध है।

उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23 के पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लगभग 555.80 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 139.84 करोड़ रुपये अधिक है।

15 सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र:

- (क) 888359 लाभार्थियों को एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना (आईएसएसएस) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत प्रति माह 1000 रुपये का पेंशन लाभ प्रदान किया गया। सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में 59% की वृद्धि हुई है।
- (ख) एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना (आईएसएसएस) के अंतर्गत पहली बार ट्रांसजेंडर को पेंशन लाभ के लिए शामिल किया गया है।
- (ग) सभी जिलों में लाभार्थियों के घर-घर जाकर आहार सामग्री एवं पूरक पोषाहार सामग्री का वितरण किया जा रहा है।
- (घ) सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे।
- (ड) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो-टैगिंग की जा रही है।
- (च) सभी विकलांग व्यक्तियों को मोटर चालित तिपहिया साइकिलें प्रदान की जाएंगी, जिससे 100% संतुष्टि स्तर प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2022-23 के लिए सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र हेतु पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लगभग 198.07 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 4.93 करोड़ रुपये अधिक है।

16. जनजाति कल्याण:

- (क) गुर्जर और बकरवाल छात्रों और अ.ज.जा. छात्रों को मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का 100% कवरेज डीबीटी के माध्यम से 100% संवितरण के साथ 2022-23 में पूरा होने की संभावना है।
- (ख) 2022-23 में 14 दुग्ध गांवों की स्थापना की जाएगी।
- (ग) 29 क्लस्टर मॉडल गांव स्थापित किए जा रहे हैं और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- (घ) 2022-23 में 3.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सात ट्रांजिट आवास/आश्रय शेड बनाए जाएंगे।
- (ङ) छह एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।

जनजातीय कार्यों के लिए, वर्ष 2022-23 के पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लगभग 282.23 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन के समान है।

17. कश्मीरी प्रवासियों को राहत और पुनर्वास:

- (क) पीएम पैकेज/पीएमडीपी-2015 के अंतर्गत 1025 पारगमन आवास इकाइयां पहले ही पूरी हो चुकी हैं/काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं। 1488 इकाइयां पूर्णता के विभिन्न चरणों में हैं और पारगमन आवास की 2744 इकाइयों पर काम शुरू कर दिया गया है और 2022-23 में पूरा होने की उम्मीद है।
- (ख) पीएम पैकेज/पीएमडीपी-2015 के अंतर्गत कश्मीरी प्रवासियों के लिए बनाए गए 6000 पदों में से 4678 पद पहले ही भरे जा चुके हैं और शेष पदों को भरा जा रहा है।
- (ग) 2022-23 में सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) के अंतर्गत खाद्यान्न, नकद सहायता आदि प्रदान करना जारी रहेगा।

उपरोक्त पैकेज के लिए, वर्ष 2022-23 के राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लगभग 1188.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 466.89 करोड़ रुपये अधिक है।

18 युवा सशक्तिकरण, रोजगार और उद्यमिता:

- (क) स्वरोजगार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- (ख) नियोक्ता और नौकरी चाहने वालों के लिए एकल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एनसीएस पोर्टल के समान रोजगार/नौकरी पोर्टल विकसित किया जाएगा।

- (ग) औवरसीज रोजगार निगम को पुनर्जीवित किया जाएगा।
- (घ) युवाओं को सशक्त बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने तथा आजीविका उत्पन्न करने के लिए , “मिशन युवा कार्यक्रम” के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- (ङ) निजी क्षेत्र में रोजगार सुविधा और स्वरोजगार के लिए उद्यमिता क्षमता निर्माण के प्रशिक्षण के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा।
- (च) अधिक युवाओं को अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए बैंक वित्त के माध्यम से मुद्रा/जीईसीएल और अन्य वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
- (छ) युवा स्टार्ट-अप/प्रारंभिक पूंजी/महिला रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार उपाय के रूप में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- (ज) ऊष्मायन/नवीनीकरण केंद्रों की स्थापना के लिए पर्याप्त प्रावधान रखा गया है।

19 कौशल विकास:

- (क) वर्ष 2022-23 के दौरान छात्रावास ब्लॉक का निर्माण और विभिन्न सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध की जाएगी।
- (ख) वर्ष 2022-23 में प्रशिक्षुओं के लिए आधारभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु विभिन्न सरकारी आईटीआई में वर्कशॉप ब्लॉक/कक्षाओं का निर्माण कार्य किया जायेगा।

20. खेल पहलें:

- (क) जम्मू-कश्मीर सरकार युवाओं को जोड़ने के लिए खेल गतिविधियों पर मुख्य ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान 17 लाख से अधिक युवाओं ने विविध खेल गतिविधियों में भाग लिया और 1.26 लाख युवाओं ने विभिन्न खेल गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- (ख) देश के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने और प्रतिभाशाली एथलीटों को अवसर प्रदान करने के लिए 17 खेल विधाओं में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी की जाएगी।
- (ग) विभिन्न खेल विधाओं में 7.50 लाख के लक्ष्य के साथ खेल गतिविधियों में बड़े पैमाने पर युवाओं को शामिल करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- (घ) जम्मू-कश्मीर में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, सॉफ्ट टेनिस, हैंडबॉल, थांग -टा, कयाकिंग और कैनोइंग, बेसबॉल और जिमनास्टिक में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी की जाएगी।

- (ड) गुलमर्ग और पहलगाम में संबंधित खेल संघों के माध्यम से बर्फ और बर्फ आधारित खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
- (च) सभी 20 जिलों में जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 221 खेल के मैदान/क्रीड़ा स्थलों का निर्माण किया जाएगा।
- (छ) 2022-23 के दौरान 157 खेल मैदानों का निर्माण/ स्टेडियमों/भवनों का उन्नयन किया जाएगा।

युवा सशक्तिकरण, रोजगार, उद्यमिता, कौशल विकास और खेल गतिविधियों के लिए वर्ष 2022-23 के पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लगभग 312.57 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जो कि पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 19.72 करोड़ अधिक है।

21 वानिकी और पर्यावरण:

- (क) 2022-23 के दौरान 1.35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 26.50 लाख पौधे ग्राम पंचायतों में हरित संपत्ति बनाने के लिए ग्राम पंचायत वृक्षारोपण समितियों (वीपीपीसी) की सक्रिय भागीदारी के साथ लगाए जाएंगे।
- (ख) वर्ष 2022-23 के दौरान हरियाली एवं वन तथा वृक्ष आच्छादन बढ़ाने की कम लागत वाली पद्धति के अंतर्गत 50 लाख से अधिक बीज/घास-के मैदान लगाने का प्रस्ताव है।
- (ग) 2022-23 के दौरान "वन बीट गार्ड वन विलेज" के अभिनव कार्यक्रम के अंतर्गत 1500 गांवों को लिया जा रहा है। यह ग्राम पंचायतों को मुफ्त पौधे, बीज गैद, घास की पर्ची प्रदान करेगा जिससे वनों के बाहर की भूमि को हरा-भरा कर दिया जाएगा।
- (घ) चिनार के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास के रूप में 2022-23 में, 20,000 से अधिक चिनार के पेड़ लगाए जाएंगे।
- (ड) वर्ष 2022-23 के दौरान वूलर झील के चारों ओर गैर-मोटर चालित रास्ते को विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है जो कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने और अतिक्रमण को रोकने में मदद करेगा।

वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लगभग 200.76 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 9.01 करोड़ रुपये अधिक है।

22 खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले:

- (क) राशन कार्ड की 100 प्रतिशत आधार सीडिंग प्राप्त कर ली गई है, इसके अलावा लाभार्थी स्तर पर 99.60% आधार सीडिंग दर्ज की गई है, जिसे 2022-23 में 100% पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- (ख) बेहतर सार्वजनिक वितरण और डिलीवरी तंत्र के लिए, 100% उचित मूल्य दुकानें/सरकारी राशन डिपो 6736 बिक्री मशीनों (पीओएस) के साथ संस्थापित कर दिए गए हैं।
- (ग) चंदनवाड़ी (अनंतनाग), कनिलो बाग (बारामूला) और संगल दान (रामबन) में नए स्टोर के निर्माण 2022-23 के दौरान किया जाएगा, जो जम्मू-कश्मीर के दूरस्थ और दूरदराज के इलाकों में विभाग के भंडारण ग्रिड को मजबूत करेगा और लगभग 1000 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता को बढ़ाएगा।

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के लिए वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लगभग 306.26 करोड़ रुपये आवंटन प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 3.40 करोड़ रुपये अधिक है।

23 विज्ञान और प्रौद्योगिकी:

I. विज्ञान जागरूकता पहल:

- (क) 2022-23 में 15 विज्ञान लोक-प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- (ख) 2022-23 के दौरान +10, +12 और स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर पर छात्रों को 150 छात्रवृत्तियां देने के अलावा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार/फैलोशिप भी शुरू की जाएंगी।
- (ग) 2022-23 के दौरान कश्मीर संभाग के अनंतनाग, बांदीपोरा, बडगाम और जम्मू संभाग के राजौरी, कठुआ और डोडा जिलों में अरोमा नकदी फसलों की शुरुआत की जाएगी।
- (घ) उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, श्रीनगर के निर्माण का कार्य 2022-23 में शुरू होने की संभावना है।

II- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा:

- (क) पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 375 सोलर वाटर पंप स्थापित किए जाएंगे, जिससे 47159 व्यक्तियों को बिजली लाभ, 18750 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष कृषि लाभ और 160000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष कृषि लाभ मिलेगा।

- (ख) जम्मू सोलर सिटी मिशन के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र में कुल 200 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर पावर प्लांट वर्ष 2022-23 में 50000 घरों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे 2 लाख लोगों की आबादी को फायदा होगा।
- (ग) जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत, वर्ष 2022-23 कुल 12 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों को में 48000 किलोवाट के जलविद्युत क्षेत्र को खत्म करने वाले 200 सरकारी भवनों को प्रदान किया जाएगा।
- (घ) श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत, कुल 4 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों को 2022-23 में 16000 किलोवाट के जलविद्युत क्षेत्र में 70 सरकारी भवनों को उपलब्ध कराया जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 127.91 करोड़ रुपये का आवंटन प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 22.00 करोड़ रुपये अधिक है।

24. वित्तीय सुधार/ई-गवर्नेंस पहल:

- (क) राजभवन सहित सिविल सचिवालय में ई-ऑफिस लागू कर दिया गया है। इसे 2022-23 में जम्मू-कश्मीर के सभी कार्यालयों में लागू किया जाएगा।
- (ख) सभी कर्मचारियों द्वारा वार्षिक संपत्ति विवरणी अपलोड करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली बनाई गई है।
- (ग) सभी कर्मचारियों के संबंध में ऑनलाइन वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रणाली बनाई जाएगी।
- (घ) वर्चुअल इंसपेक्शन सिस्टम को मजबूत करने के साथ ई-ऑडिट शुरू किया जाएगा।

25. सुरक्षा संबंधी गतिविधियां:

- (क) जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में 10,109 सामुदायिक/व्यक्तिगत बंकरों का निर्माण किया जा रहा है।
- (ख) सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) के तहत सीआरपीएफ/जेल कर्मचारियों को अल्पकालिक सुरक्षा संबंधी कार्य और अल्पकालिक बुनियादी सुविधाएं ली गई हैं।
- (ग) 2022-23 में श्रीनगर में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण शुरू किया जाएगा।
- (घ) पुलिस थानों के डिजीटलीकरण और पुलिस थानों में सीसीटीवी संस्थापन के लिए पर्याप्त प्रावधान रखा गया है।

26. चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान:

- (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मूल अनुदान 1,08,621 करोड़ रुपये था। 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक वर्ष के दौरान 18,860.3234 करोड़ रुपये की राशि आवश्यक सेवाओं और उद्देश्यों पर खर्च को चुकाने के लिए इस अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर की संचित निधि से संबंधित मांगों के तहत अनुदान से अधिक की निकासी की जाएगी। डीए में वृद्धि दर के कारण वेतन में वृद्धि, और पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों सहित अन्य राजस्व व्यय, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत पूंजी आवंटन में वृद्धि, पीएमजीएसवाई, नाबार्ड ऋण घटक, पीएमएवाई-यू, जनजातीय उप योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और आंतरिक ऋण/अर्थोपाय और ऋण अग्रिम/ओवरड्राफ्ट के लिए बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए यह काफी हद तक जरूरी हो गया था।
- (ख) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक कार्य प्रभाव की अवधि के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से 18,860.3234 करोड़ रुपये के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए पूरक जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक संख्या (01) को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

27. जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान:

- (क) 2022-23 की कुल प्राप्तियां 1,12,950 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। जिनमें से 1,02,322 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियां हैं, 10,628 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्तियां हैं और 29,200 करोड़ रुपये अर्थोपाय और ऋण अग्रिम हैं। कर और गैर-कर दोनों का स्वयं का राजस्व 25,314 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसके अलावा, 35,581 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता के रूप में और 29,750 करोड़ रुपये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को सीएसएस/पीएमडीपी के रूप में दिए जाने हैं।
- (ख) इन प्राप्तियों को देखते हुए इसमें से कुल व्यय 1,12,950 करोड़ रुपये, पूंजीगत व्यय 41,335 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 71,615 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- (ग) जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक संख्या (02) को 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी अवधि के लिए जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि से और उसमें से 142150.0987 करोड़ रुपये के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

28. राजकोषीय संकेतक:

- (क) 2022-23 के लिए कर/जीडीपी अनुपात 8.18 प्रतिशत अनुमानित है जो पिछले वर्ष के 8.17% से अधिक है।
- (ख) 2022-23 के लिए ऋण/जीडीपी अनुपात 50.84% है।

(ग) वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 203716 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% की वृद्धि दर्शाता है।

29. अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं सदन में अनुपूरक बजट (01.04.2021 से 31.03.2022 के लिए), और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2022-23 के बजट को आगे विचार के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

**Supplementary Demands for Grants of the Union Territory of
Jammu and Kashmir (with Legislature) for 2021-22 and
Budget for 2022-23**

Speech of

Nirmala Sitharaman

Minister of Finance

Mr. Speaker Sir,

1. Hon'ble Members of this August House are aware that in accordance with "The Jammu and Kashmir Re-organization Act, 2019" with effect from 31.10.2019, the Union Territory of Jammu and Kashmir continues to be under the President's Rule vide Gazette Notification S.O. 3937(E) dated 31.10.2019. The powers of the legislature of the Union Territory of Jammu and Kashmir are exercised by or under the authority of the Parliament.
2. After the historic transformative changes in August, 2019, the Union Territory of Jammu and Kashmir is poised to become the latest success story among other States/ Union Territories and model of socio-economic development for the Country. The concept of One Nation, One Constitution and One Flag has been adopted in the Union Territory of Jammu and Kashmir. All unjust and discriminatory laws have been removed. Besides all the central laws as provided under "The Jammu and Kashmir Re-organization Act, 2019" have been implemented. All sections of the people in Jammu and Kashmir are treated with fairness and equality. The weaker sections of the society have been given suitable reservations in seeking government jobs. The persons discriminated since ages like Displaced Persons of Pakistan Occupied Jammu & Kashmir (PoJK) and Chhamb, West Pakistani Refugees, Residents of Border Areas and Kashmiri Migrants have been suitably empowered to get all the benefits.
3. The domicile rules have been notified and domicile certificates are being issued. The jobs for local youth have been protected.
4. **Strengthening Grass-root Democracy:**
After successful implementation of 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, and conduct of Panchayat/Urban Local Body, District Development Council & Block Development Council elections, the main focus of the Government is to empower these Local Body Institutions with 3Fs (Funds, Functions and Functionaries). The Government is providing Rs.1,000 crore as grant to 4290 Gram Panchayats , Rs.200 crore to 20 District Development Councils (DDCs) @ Rs.10 crore to each District Development Council (DDC), Rs.71.25 crore to 285 Block Development Councils (BDCs) @ Rs.25 Lakh to each Block Development Council (BDC) and Rs.313 crore to Urban Local

Bodies for initiating developmental activities in rural and urban areas. 27 functions have been transferred to Panchayats and functions of 7 departments to Urban Local Bodies. Nearly Rs.1,727.50 crore have been devolved under MGNREGA, 14th Finance Commission, Midday Meal Scheme and Integrated Child Development Scheme (ICDS) to the Panchayats. Rs.1,455.62 crore have been devolved to Urban Local Bodies in last two years. 1,889 Panchayat Accounts Assistants have been recruited.

5. Transforming Governance:

- a) The objective of the government is to provide transparent, responsive and accountable governance. The Government of Jammu and Kashmir is focusing on unique initiatives of “Back to Village”, “My Town My Pride”, “Jan-Abhiyan” & “Block Divas” for bringing government programmes and initiatives at the door steps of the people.
- b) A massive public outreach programme was conducted across Jammu and Kashmir with as many as 73 Union Ministers and various Parliament Committees visited all the districts for public interactions and gathered grass-root level feed-back on government policies. Interactions were held with representatives of Panchayati Raj Institutions, other important stakeholders from trade, industry etc., over a period of two months which is expected to improve governance and implementation of various developmental schemes and initiatives.
- c) The introduction of principles of financial prudence, transparency and zero tolerance to corruption have revolutionized the project implementation and enhanced financial inclusion and social equity. Several important reforms have been undertaken to ensure transparency and accountability in the administration. Today a fear-free, corruption-free system of governance has been established through a paperless, faceless procedural framework. No work is allotted without following tendering process and without having Administrative Approval/Technical sanction. No bill is passed without geo-tagging of photographs through PROOF (Photographic Record of On-site Facility) application and physical verification of works. Every single penny is now spent for the welfare of the people. With the help of “EMPOWERMENT”(Enabling Monitoring & Public Overview of Works being Executed and Resources for Meaningful Transparency)/JANBAGHIDARI (janbaghidari.nic.in) an Information Technology enabled programme, the common citizens of the Union Territory of Jammu and Kashmir can overview works/projects being implemented in their areas and become a partner in the process of development.
- d) Union Territory of J&K has become the first among States/Union Territories in the country to have District Good Governance Index for assessing the efficiency of public delivery system at district level. This index is expected to foster transparency and accountability in the basic unit of governance and fulfill the aspirations of citizens. Best practices are being identified in each district for replication in others.

- e) A historic initiative “Aapki Zameen Aapki Nigrani” has been launched in which the scanned data of Jamabandi, Girdawari, Mutation and Musavi of all the 20 districts of the Union Territory of J&K have been made available to the common citizens. Taking another step towards empowerment of land owners, land passbooks have been issued in three languages.

6. COVID Management:

Jammu and Kashmir has emerged as a model for the entire country in the management of the COVID 19 pandemic. With 100% vaccination of the eligible population, Union Territory of J&K has crossed the 20 million vaccine dose mark. The vaccination in respect of 15-17 age group has been started all across the Union Territory and 100% target will be achieved soon.

Oxygen Generation Plants have increased by 87 with 90,300 Litres Per Minute (LPM) capacity addition. Two 500 bedded hospitals were setup by DRDO in Jammu and Srinagar to fight covid-19 pandemic.

Government of Jammu & Kashmir has introduced “Saksham” Scheme for the families who have lost their only breadwinner due to covid. Under the said scheme, scholarship of Rs.20,000 per annum is provided to school going children and Rs.40,000 per annum to college going students through Direct Benefit Transfer (DBT). Rs.1,000 per month to surviving spouse and eldest dependent family member is also provided under the scheme.

7. Employment:

In the last one and half year, 11,000 appointments have been made in various government departments in a fair and transparent manner, which was unprecedented in the history of Union Territory of Jammu and Kashmir. For the first time, persons from disadvantaged and poor sections have secured jobs on the basis of merit turning their dreams into reality. Further, 20,323 additional posts at various levels have been identified and referred to the Jammu and Kashmir Service Selection Board for recruitment. Besides, 1,850 appointments have been made in J&K Bank at various levels in a fair and transparent manner. As many as 1,37,870 youth have been provided assistance in their entrepreneurial ventures under various self-employment schemes and programmes.

8. Accelerating Development:

- (a) The pace of execution of projects under Prime Ministers Development Package (PMDP) has been accelerated. Expenditure has reached to Rs.36,112 crore. 25 Projects have been completed / substantially completed and another 4 projects are likely to be completed by end of the current financial year.
- (b) Against 9,229 works/projects under various sectors/schemes completed in 2018-19, 12,637 works/projects were completed in 2019-20. 21,943 works/projects have been completed in 2020-21. During the current financial year 2021-22 already 25,446 works/projects under different sectors/schemes have been completed. This shows that more and more

developmental works are getting completed since 2019, despite challenges of Covid-19 Pandemic and other constraints.

- (c) Speaker sir, let me inform this August House that Government of India and Government of Jammu and Kashmir are taking serious efforts to accelerate the pace of development in the Union Territory of Jammu and Kashmir. The road connectivity is extremely essential for the development of any region. Till the year 2018, on an average, 1,500 to 1,600 kilometers of road length used to be constructed each year, the same has now more than doubled to 3,200 kilometers. Union Territory of J&K is marching ahead with its ambition of road to every village. With the availability of better road length & opening of Qazigund-Banihal tunnel now travel time between Srinagar and Jammu has reduced from 10 hours to 5 hours.
- (d) It is expected that Kashmir will be connected to rest of the country through rail network by the next year. Elevated Light Metro Rail in Jammu & Srinagar cities is expected to be rolled out in 2022-23. The project is likely to be completed by 2026. This will reduce the traffic congestion in Srinagar & Jammu cities.
- (e) International flights have been started between Srinagar and Sharjah. Besides, two new Airport Terminals are coming up at Jammu and Srinagar. Cargo facility has been provided at Jammu and Srinagar Airports for the convenience of farmers and businessmen.
- (f) Road infrastructure by way of construction of mega highways and tunnel projects is in progress. A number of highway projects are presently under execution. Work on Srinagar-Jammu National Highway is being completed in next 2-3 years bringing much respite for the people of the Union Territory of J&K.
- (g) The work on Z-Morh Tunnel on Srinagar- Sonmarg road is going on at the brisk pace, which will provide an opportunity to tourists to visit Sonmarg in winter as well. Work on Zojila Tunnel on Srinagar-Leh road has commenced. With the construction of six-lane Delhi-Amritsar-Katra Expressway, the travel time from Delhi to Mata Vaishno Devi Shrine will be reduced to 6 hours only.
- (h) Speaker sir, in Jammu & Kashmir only 3,500 MW of electricity has been generated since independence. By our efforts Union Territory of J&K is all set to double hydroelectric power generation in next three years. In this direction, 5 mega hydro power projects viz Ratle (850MW), Kirthai-II (930 MW), Sawalakote (1,856 MW), Dulhasti-Stage II (258 MW) and Uri-I Stage-II (240 MW) with total capacity of 4,134 MW have been taken up for execution in collaboration with NHPC. The likely investment in these projects is Rs.34,882 crore and on completion will make Union Territory of J&K power surplus. The delay in execution of the projects has been eliminated and the pace of execution accelerated. On-going Hydro Electric Projects (HEPs) Kiru (624 MW), Kawar (540 MW) and Pakaldul (1,000 MW) are

being developed through the Joint Venture and by 2022-23, major civil and electro-mechanical works of these projects will be completed.

- (i) By August, 2022 all rural Households, Community Centres, Ashramshallas and other government offices will be provided with piped water supply.

9. Industrial Development:

Despite challenges, efforts are underway for turning Jammu and Kashmir into a preferred destination for industrial investment and opportunities. After implementation of the new industrial scheme, under the guidance of Hon'ble Prime Minister and Hon'ble Home Minister, 4,226 investment proposals worth Rs.47,441 crore have been received which may further upscale with the passage of time. The land use change policy which was a major impediment for the industrial development of the region has been simplified which is likely to attract more investment. Jammu and Kashmir recently hosted the first ever historic Real Estate Summit in December 2021, in which investment proposals worth Rs.18,300 crore were received. Similarly Jammu and Kashmir was a major attraction in Dubai Expo, held in January, 2022. Global investors exhibited keen interest for investing in Jammu and Kashmir and investment proposals worth Rs.3,000 crore were finalized. Significant steps have been taken towards ease of doing business and all required services have been made available online through single window clearance system.

10. Economic Recovery Post Covid-19 Pandemic:

- a) As result of wide range of measures taken for covid management, the year 2021-22 started with fervent hope of faster economic recovery although the fear of third wave loomed large, threatening to affect the economic activities. Jammu & Kashmir economy has comparatively performed better during 2020-21 as compared to other States/Union Territories. The economy is expected to grow by 7.5% on current prices during 2021-22.
- b) The SGST collection has been Rs.1,897 crore upto February, 2022 against Rs.1,389 crore upto February, 2021 which is 36.57% higher than previous year (2021) over the same period. The IGST settlement has been Rs.3,917 crore upto February, 2022 against Rs.2,921 crore upto February, 2021 which has registered a growth of 34.09% over previous year (2021) in the same period. Stamp Collection has been Rs.398 crore upto February, 2022 against Rs.236 crore upto February, 2021 which is 68.64% higher than previous year (2021) over the same period. The collection of revenue on account of sale of petrol and diesel under the "Jammu & Kashmir Motor Spirit and Diesel Oil (Taxation of Sales) Act", upto ending February, 2022 has been Rs.1,736 crore against Rs.1,320 crore for the corresponding period of previous year ending February, 2021 registering a growth of 31.51%. Excise collection has been Rs.1,444 crore upto February, 2022 against Rs.1,186 crore upto February, 2021 which is Rs.258 crore more than previous year (2021) registering a growth of 21.75% over previous year (2021) during the same period. Briefly speaking, tax collection has been showing significant growth

and resilience which is pointer to the fact that Union Territory of J&K is on the path of rapid economic recovery.

- c) The tourism sector is also registering increase in footfall of tourists. Around 1.43 Lakh tourists visited Kashmir in December, 2021 which is highest in the last 7 years. From September 2021 onwards around 72.09 lakh tourists including pilgrim tourists visited Jammu & Kashmir which is much higher than the previous years. Winter season has witnessed 100% high-end hotel occupancy in Srinagar and at prominent tourist destinations particularly Gulmarg and Pahalgam.
- d) Export of dry & fresh fruits is picking up and by end of January, 2022 about 17.09 Lakh Metric Ton have been exported.

11. Financial inclusion:

- a) Speaker Sir, the Government of Jammu & Kashmir has taken well calibrated steps to revive economy post covid pandemic. The Economic Revival Package of Rs.1,350 crore announced in September, 2020 has been well received and so far Rs.750 crore have been provided as 5% interest subvention in case of 3.44 Lakh account holders/ borrowers for 6 months, besides implementation of other measures of the said package.
- b) Under Atma Nirbhar Bharat Abhiyan, 60736 borrowers have been benefitted under Guaranteed Emergency Credit Line -1 (GECL-1) involving Rs.1,878 crore. Free rice was provided to 98,566 individual beneficiaries and pulses to 31,069 families. 289 borrowers have been benefitted under business support loan involving Rs.74.37 crore. Special credit facility for street vendors with an initial working capital of Rs.10,000 has been disbursed to 14,514 beneficiaries under PM-SVANidhi Scheme. Rs.5,841 crore has been disbursed to 8.27 Lakh KCC (Crop) account holders and Rs.637 crore to 1.26 Lakh KCC-Animal Husbandry & Fisheries (AH&F) account holders. Rs.3,464 crore under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) loan has been disbursed to 1,52,703 beneficiaries.
- c) While 23,434 loan cases involving Rs.407 crore for the youth identified during “Back to Village” programme have been sanctioned, 19,645 youth have been already provided loan of Rs.336.79 crore through banks for starting their own business ventures among which 6,679 women entrepreneurs are included.

12. Direct Benefit Transfers:

Government of Jammu & Kashmir intends to achieve 100% coverage under all individual beneficiary schemes, particularly under various scholarship schemes during 2022-23. Union Territory administration is committed to achieving 100% saturation in respect of all beneficiary oriented schemes, besides 100% Aadhar seeding. This year more than Rs.2,017 crore has been disbursed to more than 65 lakh beneficiaries through Direct Benefit Transfer (DBT) under various social security schemes. 2,72,465 beneficiaries have been added to extend benefits of social

security over past few years. Assistance of Rs.1,000 per month for four months has been provided to more than 1.66 lakh workers. Over 70,000 destitutes, Slum Dwellers, Migrant Labourers were provided with ration.

13. Budget 2022-23:

- 13.1 The budget 2022-23 for Union Territory of Jammu & Kashmir shall focus on Good Governance, Deepening Grass-root Democracy, Accelerated Development & Inclusive Growth, Facilitating Investment and Industrial growth, Infrastructure Development for Improving Quality of Life and Employment, Youth Initiatives & Women Empowerment and Broadening social inclusion.
- 13.2 The budget 2022-23 for Union Territory of J&K shall again cross Rs.1 lakh crore mark, an indicator of our commitment to make Union Territory of J&K a model of development. The total budget estimates for 2022-23 are Rs.1,12,950 crore (net) out of gross budget of Rs.1,42,150 crore (including ways and means advance of Rs.29,200 crore), of which developmental expenditure is of the order of Rs.41,335 crore.
- 13.3 The capital component of the budget has increased substantially. The expected revenue receipts are Rs.1,02,322 crore whereas revenue expenditure is expected to be Rs.71,615 crore thereby making available revenue surplus for capital expenditure to the tune of Rs.30,707 crore.
- 13.4 The capital receipts are projected at Rs.10,628 crore and capital expenditure is expected to the tune of Rs.41,335 crore which is 37% of the earmarked budget and will be spent on infrastructure development projects.

14. Socio-Economic Development:

14.1 Agriculture, Horticulture and Sericulture Sector:

- (a) Government of Jammu & Kashmir aims at doubling of the farmers income by encouraging cultivation of high yield/high density crops, use of modern technology and laboratory tested pesticides and other measures.
- (b) 16,960 farmers will be benefitted by covering 15,240 hectare area by providing infrastructure facilities like 3,200 pump sets, 898 borewells and 10,000 drip and sprinkler irrigation system with a provision of Rs.55.80 crore.
- (c) 8.93 Lakh farmers will be benefitted by distribution of High Yield Varieties/Hybrid seeds, with an investment of Rs.23.97 crore .
- (d) 36,000 farmers will be trained for capacity building with a provision of Rs.27 crore.
- (e) 33,200 farmers will be benefitted by providing farm machinery with a provision of Rs.81 crore.

- (f) 44,204 farmers will be benefitted under area expansion by providing 2 crore vegetable seedlings and expansion of 45 hectare under Potato, 756 hectare under organic farming and 250 hectare under spices with a financial assistance of Rs.6 crore.
- (g) 22,000 farmers will be benefitted by establishment of 11 big/ small mandies with a provision of Rs.1.60 crore.
- (h) The irrigation for 8,670 hectare of land will be restored by maintenance of field channels for which an amount of Rs.30 crore has been provisioned.
- (i) 12,800 farmers will be covered by way of formation of Farmer Producer Organisations (FPOs) with a financial assistance of Rs.80 lakh.
- (j) While Controlled Atmosphere storage capacity of around 1.70 Lakh Metric Ton has been already established, another 30,000 Metric Ton is likely to be added by the end of the current financial year. 50,000 Metric Ton Controlled Atmosphere storage capacity is targeted for completion during 2022-23. The focus will be to reach a Controlled Atmosphere capacity of about 5 Lakh Metric Ton in next three years.
- (k) Government of Jammu & Kashmir in collaboration with National Agricultural Cooperative Marketing Federation (NAFED) is undertaking High Density Plantation over an area of 5,500 hectare in next five years. Accordingly a new scheme of High Density Plantation was launched in March, 2021 which apart from apple also includes other crops grown in Jammu and Kashmir. The target for 2022-23 is to cover 400 hectare under High Density Plantation for apple and 1,000 hectare under sub-tropical fruits plants.
- (l) A Mega High Density Plantation Nursery under government sector for sub-tropical fruit plants on an area of 800 hectare at an estimated cost of Rs.12.30 crore is being established at Chakrohi Jammu, besides 10 High Density Plantation Nurseries are targeted for establishment in private sector during 2022-23.
- (m) Under "PARVAZ" scheme, subsidy on anti-hail net is proposed to be taken in 2022-23 to tackle the issue of fruit crop damage due to hail.
- (n) Subsidy will be provided for up-gradation of Micro Food Processing Units and also for establishing new food processing units as per One District One Product (ODOP) list.
- (o) 5 Silkworm seed units & Chawki rearing centres for production of quality Silkworm seed will be up-graded with a provision of Rs.1.89 crore.
- (p) 2 Cocoon Auction Markets for creation of marketing facilities will be constructed for which an amount of Rs.86.13 lakh has been provisioned.
- (q) 400 farmers will be provided with rearing appliances to assist in rearing for increasing cocoon yield with a provision of Rs.1 crore.

For Agriculture and Horticulture Sectors, an allocation of about Rs.1,950.04 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2022-23 which is Rs.310.08 crore more than previous year's budget allocation.

14.2 Animal, Sheep Husbandry and Fisheries Sector:

- (a) Around 2,000 dairy units will be established during financial year 2022-23 with creation of direct employment for around 5,000 people.
- (b) Support will also be extended in milk processing sector for private entrepreneurs in the form of bulk milk coolers, milk processing/paneer making machines, marketing facilities which include milk ATMs & milk transportation vans, milking machines and dairy farm waste management. Focus will also be given to cover female entrepreneurs and other reserved category beneficiaries.
- (c) In order to increase milk production/productivity in cattle and buffaloes, free of cost Artificial Insemination service at farmers doorsteps will be provided to 4.60 Lakh breedable dairy cows/buffaloes by conducting around 13 lakh Artificial Inseminations.
- (d) The annual milk production is expected to increase from current 2,505 Thousand Metric Ton to 2,800 Thousand Metric Ton.
- (e) Around 1,200 sheep/goat units will be established with creation of employment opportunities for around 2,400 people.
- (f) 200 elite cross breed imported merino sheep will be introduced for genetic upgradation of local sheep for production of more than 8,000 elite lambs. This will lead to an increase in carcass yield from prevalent 18 kg to 21 kg besides incrementing fine wool production from existing 2 Kg to 2.5 Kg per sheep.
- (g) 44 mobile veterinary clinics are proposed to be operationalized to provide doorstep delivery of veterinary health care and breeding services. Around 78 lakh livestock and 5 crore poultry birds will be vaccinated against different scheduled animal diseases.
- (h) Under Integrated Poultry Development Scheme, local entrepreneurs will be encouraged by providing 50% subsidy for starting a new poultry farm along with insurance of poultry birds, purchase of poultry farm equipments/machinery, poultry processing equipments, rendering units and poultry transportation vehicles.
- (i) 35,000 backyard poultry units are projected to be established during 2022-23.
- (j) Fodder cultivation will be incentivized with establishment of fodder demonstration plots, distribution of improved fodder mini-seed kits, fodder mechanization and establishment of Cattle Feed Plants/Silage Plants/Fodder Block making machines and Hydroponic Fodder Production.

- (k) Avian Influenza testing facility will be provided across the Union Territory of J&K for prompt testing of suspected samples.
- (l) Fish production is expected to enhance from current 24,000 Metric Ton to 33,000 Metric Ton along with doubling of the trout production from 1,400 Metric Ton to 2800 Metric Ton during 2022-23.
- (m) Emphasis will be laid on establishment of intensive fish rearing units based on latest technological interventions like Biofloc and Re-circulatory Aquaculture systems.
- (n) To make trout accessible to consumers throughout the country and outside, focus will be laid on establishment of fish processing and packaging units across Jammu & Kashmir. This will boost the production and remuneration to fish farmers.
- (o) Under “PARVAZ” scheme, subsidized air freight facility will be provided to push trout exports to various cities and Middle East Countries.
- (p) Mass awareness campaign will be launched with an emphasis on branding of trout and promotion of its export.

For Animal, Sheep Husbandry and Fisheries Sectors, an allocation of about Rs.391.90 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2022-23 which is Rs.38.86 crore more than previous year’s budget allocation,

14.3 Health and wellness:

- (a) A universal health coverage scheme in convergence with Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) to provide free of cost insurance cover upto Rs.5 lakh per household per year is progressing smoothly. 55.56 lakh beneficiaries have been already registered. 1,592 medical packages as approved under AB-PMJAY are accessible to the beneficiaries of Jammu & Kashmir Health (SEHAT) Scheme. The pace of coverage will be accelerated during 2022-23 to achieve the desired target with objective to cover all the residents of Jammu & Kashmir under this insurance cover.
- (b) Action plan has been framed to bring down the Infant Mortality Rate (IMR) to a single digit for which necessary provision has been earmarked under National Health Mission (NHM) budget.
- (c) Government of Jammu & Kashmir intends to start first Batch of MBBS classes in both the new Medical colleges at Handwara (Kupwara) and Udhampur during academic session 2022-23, thereby increasing the overall intake capacity to 1,300 MBBS seats in Union Territory of J&K.

- (d) For better patient management and reduction of referrals, availability of doctors and specialists in new Government Medical Colleges will be increased.
- (e) All the remaining 7 Nursing colleges are targeted for completion during 2022-23.

For Health and Medical Education Sector, an allocation of about Rs.1,484.72 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2022-23.

14.4 Rural Economy:

- (a) Under MGNREGA, 426 lakh persondays are targeted to be generated during 2022-23. 60,000 job cards are proposed to be issued based on demand and 1 lakh development works of different nature will be initiated and expected to be completed.
- (b) Under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA), 1,500 elected representatives will be provided exposure visit outside Union Territory of J&K. Capacity building and refresher training will be imparted to 1,12,000 participants (PRIs/Line Department Officers/Officials) in phased manner. Internet connectivity will be provided to all the gram panchayats across Union Territory of J&K. 400 new and 300 existing panchayat ghars will be taken up for construction and renovation respectively.
- (c) 54,000 houses will be constructed under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAY - G) during 2022-23.
- (d) Under Swachh Bharat Mission-Gramin (SBM-G), 87,250 Individual Household Latrines (IHHL) and 2,500 Community Sanitary Complexes (CSC) are targeted to be constructed during 2022-23.
- (e) Under National Rural Livelihood Mission (NRLM), 21,194 Self Help Groups (SHGs) are proposed to be formed during 2022-23, 20,000 revolving fund and 18,000 Bank linkage are targeted to be covered.
- (f) Under Himayat (Deen Dyal Upadhyaya-Gramin Kaushalya Yojana), the skill training to 14,067 youth and 9,847 job placements are proposed to be taken during 2022-23.
- (g) Construction of residential/office accommodation for members of District Development Council/Block Development Council/Panchayati Raj Institution (DDC/BDC/PRI) has been initiated. A provision of Rs.176.32 crore has been kept for 2022-23.

For Rural Sector, an allocation of about Rs.4,627.85 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2022-23 which is Rs.327.40 crore more than the previous year's budget allocation.

14.5 Power Sector:

- (a) Government of Jammu & Kashmir is committed to strengthen power infrastructure with a view to making Jammu & Kashmir power surplus, remove all supply constraints and provide 24X7 quality power.
- (b) The transformation capacity has been added by 150% over the last 2 years. The focus under transmission sector is on enhancing the existing capacity and also to increase the carrying capacity of vital transmission lines by way of construction of new/augmentation of existing grid sub-stations and replacement of existing Aluminum Conductor Steel Reinforced (ACSR) cables by High Temperature Low Sag (HTLS) conductors.
- (c) The transmission capacity is expected to reach 12,655 MVA by March, 2022 and the transmission capacity at 220/132 KV level and 132/33 KV level is expected to be increased by 520 MVA and 580 MVA respectively in 2022-23.
- (d) About 160 Circuit kilometers of existing ACSR is being replaced by HTLS Conductor to increase the carrying capacity by 1.75 times besides installation of towers at various locations for ground clearance.
- (e) Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) a new reforms based and results linked scheme introduced by Ministry of Power (GoI) aimed at reduction of Aggregate Technical and Commercial (AT&C) losses, 100% pre-paid metering, reduction of Average Cost of Service-Aggregate Revenue Realized (ACS-ARR), developing modern DISCOMs and Leveraging Artificial Intelligence besides focus on operational efficiency will be rolled out and made operational in Union Territory of J&K during 2022-23.
- (f) Reliable and Quality power supply will be provided to consumers by way of creation/augmentation of 11/0.33 KV critically overloaded sub-stations and improvement/modernization of HT/LT lines.
- (g) Enforcement drive against power pilferages will be further intensified and made a regular feature to reduce losses and also ensure revenue realization.
- (h) To increase billing efficiency and revenue realization, thrust would be laid on IT & On-line billing/collection. Moreover, the process of Digitizing Database of Distribution Transformers and on-boarding of remaining feeders on the National Power Portal (NPP) will be completed during 2022-23.
- (i) 6 lakh Smart pre-paid meters (3 lakhs each for Jammu and Kashmir Divisions) will be installed for preventing human intervention in billing/collection and subsequent reduction in Aggregate Technical and Commercial (AT&C) losses.

For Power Sector, an allocation of about Rs.2,457.58 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2022-23.

14.6 Tourism and Culture:

- (a) Tourism sector plays a very pivotal role in the economy of Jammu & Kashmir. The Union Territory administration is focusing on promotion of tourism by vibrant campaigning and holding of national and international events for showcasing the tourism avenues available in Jammu & Kashmir.
- (b) 75 off-beat destinations have been identified across Union Territory of J&K. These destinations will be developed under run-up to 75th “Azadi Ka Amrit Mahotsav” with proper infrastructure and requisite facilities for tourists.
- (c) The unexplored Tourist destinations will be explored through Public and Private Investment model.
- (d) The potential of water based tourism activities will be capitalized by promoting adventure tourism.
- (e) Golf tourism will be promoted by holding national and international events to attract high revenue generating tourists.
- (f) World class wayside amenities and facilities will be provided besides tourism related assets will be renovated and upgraded to increase and attract the high end tourists.
- (g) Rich cultural heritage will be showcased through local film/cinema/theatre, besides promotion of local festival activities as a step towards preservation and conservation of the heritage sites of Jammu & Kashmir.

For Tourism and Culture sectors, an allocation of about Rs.604.77 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2022-23 which is Rs.78.61 crore more than previous year’s budget allocation.

14.7 Jal Shakti Department:

I. PHE Sector:

- (a) Financial year 2022-23 is the final year for achieving the objective of 100% piped water supply to each and every rural household of the Union Territory of J&K under Jal Jeevan Mission. As of now, the coverage of households with tap water Connections has reached 56.36% which is expected to touch 81% by end of the current financial year.
- (b) The coverage of households with Functional Household Tap Connection (FHTC) under the flagship programme “Jal Jeevan Mission-Har Ghar Jal” has reached 10.34 lakh out of 18.35 lakh households. The remaining households (8.01 lakh) are targeted to be completed by August, 2022.
- (c) 1,589 water supply schemes are targeted to be completed during 2022-23.

- (d) In order to ensure availability of quality water 2.50 lakh water quality tests are planned to be conducted in 2022-23. Besides National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories (NABL) accreditation of all 20 district water testing laboratories will be achieved and all sub-divisional laboratories will be registered during 2022-23.

II. Irrigation & Flood Control Sector:

- (a) 43 ongoing minor irrigation schemes under Accelerated Irrigation Benefit Programme - Prime Minister's Krishi Sinchai Yojana (AIBP-PMKSY) will be physically completed during 2022-23.
- (b) 28 thousand hectare of Irrigation Potential is targeted to be created/ stabilized during 2022-23.
- (c) Balance portion of work on Tawi Barrage costing Rs.73.34 crore is expected to be completed during 2022-23.
- (d) Flood protection works costing Rs.27.91 crore for safeguarding the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) site at Vijaypur, Jammu are targeted to be completed by 2022-23.
- (e) The work on Ujh Multi-Purpose Project (UMPP) is expected to start during 2022-23 for which Detailed Project Report (DPR) stands redesigned.

For Jal Shakti Department, an allocation of Rs.9289.15 crore has been made under Capital Expenditure for 2022-23, which is Rs.6412.71 crore more the previous year's budget allocation.

14.8 Housing and Urban Development Sector:

- (a) Under AMRUT-1.0, 76 projects are likely to be completed during the current financial year and the remaining projects will be completed during 2022-23 which include construction of multi level car parking facility at Panjtirthi Jammu, construction of 5 Nallahs of Tawi River Phase-II, Green Space at Roop Nagar etc.
- (b) Under AMRUT -2.0, City Water Action Plan will be implemented for all Urban Local Bodies (ULBs) for providing 100% secure water tap connections to each household left out in urban areas. Besides, all water bodies in urban areas will be rejuvenated in phased manner.
- (c) Under Swachh Bharat Mission (U), 16 Urban Local Bodies (ULBs) have achieved Open Defecation Free Plus (ODF+) status and the target of 25 ULBs will be accomplished by the end of current financial year. Remaining ULBs will achieve ODF+ status in 2022-23.
- (d) With the roll out of Solid Waste Management projects, nearly 70% source segregation is likely to be achieved during 2022-23.
- (e) All the uncovered areas of Srinagar, Jammu & Anantnag will be covered with sewerage/ septage treatment facilities in phased manner during 2022-23 under SBM(U)-2.0.

- (f) The establishment of Solid Waste Management Plant at Srinagar and Jammu will help in scientific disposal of about 850 Metric Ton of waste per day and also eliminate the vulnerable garbage points in both the cities besides generation of energy and production of compost/Refuse Derived Fuel (RDF), benefitting nearly 20 Lakh souls.
- (g) The establishment of decentralized processing facilities in 76 ULBs will be completed during 2022-23 and 690 Metric Ton of waste generated in these ULBs will be scientifically treated benefitting a population of nearly 14 Lakh.
- (h) Under Smart City Mission, out of 270 projects, 95 projects are likely to be completed by the end of current financial year and 80 more projects will be completed in 2022-23. These projects once completed in both the smart cities will improve the quality of life of the people by way of providing Wifi facilities, Smart health centres, installation of river vending machines, smart classrooms, TV charging stations, development of cycle tracks/hawkers zone, development of parking and space under flyovers etc.
- (i) 9 major sewerage schemes at an estimated cost of Rs.1,131.07 crore will be executed during 2022-23 and these projects are likely to be completed during 2023-24 benefitting a population of 6,20,565 souls.
- (j) 2.15 lakh LED lights in 76 ULBs, in collaboration with M/s Energy Efficiency Services Limited (EESL) are expected to be replaced and nearly, 14 Lakh souls in these ULBs will be benefitted.
- (k) Under Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (Day-NULM), 15,000 beneficiaries will be covered under self employment Component during 2022-23.
- (l) Western Foreshore Road along Dal lake will be constructed. More indigenous lake cleaning machines will be procured for dredging and cleaning of Dal Lake. 1.5 Square kilometer area will be cleared from lilly pads during 2022-23. Deweeding and Dredging will be conducted along shore line of 1.5 Square kilometer area during 2022-23. Dredging of acquired land near western side of the lake for 60,000 square meters will be achieved and subsequently converted into water bodies.

For Housing and Urban Development Sector, an allocation of about Rs.3,112.88 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2022-23 which is Rs.230.94 crore more than the previous year's budget allocation.

14.9 Education Sector:

I - School Education:

- (a) The gross enrolment ratio has shown significant improvement. The intensive enrolment drive has been initiated under "Aao School Chalein".

- (b) About 8.30 lakh eligible students at elementary level (I-VIII) under Midday Meal Scheme will be served with fortified rice for improving nutritional health of students.
- (c) Software application developed by CBSE will be utilized for monitoring implementation of Midday Meal Scheme.
- (d) NGO Akshaya Patra will be involved in serving hot cooked meal to students enrolled in schools located in urban areas of Jammu and Samba districts on a pilot basis .
- (e) 500 Kindergartens will be established in government schools for increasing enrolment, providing early child care education and enhancing numerical and foundation literacy.
- (f) 518 smart/ virtual classrooms will be established in higher secondary schools for imparting quality education to students.
- (g) 200 Vocational laboratories will be established and 40 schools having vocational laboratories will act as hubs for imparting vocational/ skill education.
- (h) 37 girls hostel buildings and 12 Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) buildings will be completed for improving residential facilities for girls and bringing about desired gender parity in education.
- (i) 8,000 meritorious tribal students will be given tablets.
- (j) Construction of two residential schools for tribals each in district Rajouri and Shopian will be taken during 2022-23.
- (k) Survey of out of school children will be conducted using “TALASH” application developed by UNICEF and appropriate steps will be taken for mainstreaming them.
- (l) Sports infrastructure will be developed in 100 schools (5 schools per district).

II - Higher Education:

- (a) 7 college buildings will be completed during 2022-23.
- (b) Centers for Invention, Innovation, Incubation and Training (CIIT) will be established at Jammu and Srinagar in collaboration with Tata Technologies during 2022-23 for skill development of students.
- (c) Higher education e-governance system will be developed in all the colleges within Jammu & Kashmir.
- (d) NAAC accreditation of 59 colleges will be completed.
- (e) Two high level Research Institutes for providing opportunity to students and faculty for high end research and innovation will be set up in 2022-23.

- (f) Nearly 20,000 undergraduate students will be covered under Skill enhancement training during 2022-23.

For School and Higher Education Sector, an allocation of about Rs.1,806.66 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2022-23 which is Rs.249.17 crore more than the previous year's budget allocation.

14.10 Road Connectivity, (Roads & Bridges):

- (a) Overall 6,000 Kilometers of black-topping of roads is expected to be achieved during 2022-23 under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)/ Cities & Towns/Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)/National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD)/ Pothole Free Roads.
- (b) 543 new projects at an estimated cost of Rs.2,237 crore to be sanctioned with NABARD funding will be taken for execution during 2022-23.
- (c) Maintenance of existing Road Infrastructure will get focused attention during 2022-23 in terms of Road Maintenance Policy 2021 approved by the Government of Jammu & Kashmir.
- (d) Government of Jammu & Kashmir has rolled out 3rd party inspection mechanism in Public works (Roads & Bridges) Department. All ongoing works will be brought under the purview of 3rd party inspection mechanism from financial year 2022-23.
- (e) Upgradation of 1,750 Kilometer road length is likely to be taken up after receiving sanction of PMGSY-III during 2022-23.
- (f) 50 bridges will be completed under Central/ Union Territory Sector schemes during 2022-23.

For Road and Bridge Sector, an allocation of about Rs.5,217.87 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2022-23.

14.11 Industries and Commerce:

- (a) The focus of the Jammu & Kashmir Industrial Policy 2021-30 is to attract new investment, creation of employment opportunities for youth, development of backward regions and nurturing of existing industrial units. Adequate provision has been kept for providing of incentives to prospective entrepreneurs as per Jammu & Kashmir Industrial Policy 2021-30.

- (b) The Government of Jammu & Kashmir is providing an enabling environment for investors to start their ventures in the Union Territory.
- (c) Rs.25 crore have been provisioned for organizing Jammu & Kashmir Global Investor's Summit including domestic/ international road shows.
- (d) Rs.150 crore have been provisioned for development of New Industrial Estates during 2022-23.
- (e) Rs.42.60 crore have been earmarked for development of new Industrial Estates at Budhi Kathua, Mearth Ghatti, Rakh Rara Swankha Morh Samba & Katli Dhaini (Samba) in Jammu division and Khonmoh, Sempora, Chandgam Tahab, Hardoo Dahrana Dooru and Hassan Noor in Kashmir division.
- (f) Rs.3.91 crore have been provisional for construction of 7 Common Effluent Treatment Plants (CETPs) in the existing Industrial Estates.
- (g) 1,354 units under Jammu & Kashmir Rural Employment Generation Programme (J&K REGP) will be established in 2022-23 involving margin money of Rs.25 crore with employment to 8124 persons.
- (h) 2,000 Cooperatives/Self Help Groups will be covered under Credit Card Scheme benefiting directly/indirectly 20,000 persons. 7% interest subvention is available for availing loan upto Rs.2 lakh by artisans under Artisan Credit Card (ACC) Scheme.

For Industries and Commerce Sector, an allocation of about Rs.555.80 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2022-23 which is Rs.139.84 crore more than the previous year's budget allocation.

15 Social Security Sector:

- (a) 8,88,359 beneficiaries were provided pension benefits at Rs.1,000 per month under Integrated Social Security Scheme (ISSS) and National Social Assistance Programme (NSAP). There has been increase of 59% of beneficiaries under social security and pension schemes.
- (b) Transgender have been for the first time included for pension benefits under Integrated Social Security Scheme (ISSS).
- (c) Distribution of dietary items and supplementary nutrition items are being made at the door step of beneficiaries in all districts.
- (d) Old Age Homes will be established in all districts.
- (e) Geo-tagging of all the Anganwadi Centers is being done in collaboration with Information Technology Department.

- (f) Motorized tricycles will be provided to all handicapped persons thereby achieving 100% saturation level for which Rs.25 crore have been provisioned.

For Social Security Sector, an allocation of about Rs.198.07 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2022-23 which is Rs.4.93 crore more than the previous year's budget allocation.

16. Tribal Welfare:

- (a) 100% coverage of pre-matric and post-matric scholarship to Gujjar and Bakerwal students and Scheduled Tribe students with 100% disbursement through Direct Benefit Transfer (DBT) is expected to be accomplished in 2022-23.
- (b) Establishment of 14 Milk villages will be taken up in 2022-23.
- (c) 29 Cluster Model Villages are being established and are at different stages of implementation.
- (d) Seven number of transit accommodations/shelter sheds with an estimated cost of Rs.3.50 crore each will be taken up in 2022-23.
- (e) Six Eklavya Model Residential Schools for Scheduled Tribe students are being established.

For Tribal Affairs, an allocation of about Rs.282.23 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2022-23 which is same as the previous year's budget allocation.

17. Relief & Rehabilitation of Kashmiri Migrants:

- (a) Under PM Package/ PMDP-2015, 1,025 transit accommodation units have been already completed/substantially completed. 1,488 units are at different stages of completion and the work on 2,744 units of transit accommodation have been initiated and are expected to be completed in 2022-23.
- (b) Out of 6,000 posts created for Kashmiri Migrants under PM Package/PMDP-2015, 4,678 posts have been already filled and remaining posts are being filled.
- (c) Providing of food grains, cash assistance, etc will continue under Security Related Expenditure (SRE) in 2022-23.

For above package, an allocation of about Rs.1,188.15 crore has been made for the year under Revenue & Capital Expenditure 2022-23, which is Rs.466.89 crore more than the previous year.

18. Youth Empowerment, Employment and Entrepreneurship:

- (a) Financial support will be provided to youth for undertaking self employment.
- (b) Employment/job portal at par with National Career Service (NCS) portal will be developed for providing single platform for employer and job seekers.
- (c) Overseas Employment Corporation will be revitalized.

- (d) To empower and provide self employment opportunities to youth, Rs.200 crore have been provisioned under “Mission Youth Programme”.
- (e) Job fairs will be conducted for facilitating jobs in private sector and training to be imported to build entrepreneurship capacities for self-employment.
- (f) More youth will be covered under MUDRA/GECL and other financial inclusion schemes through bank finance for raising their own livelihood.
- (g) As a self employment measure under Youth Start-up/Seed Capital/Women Employment Programme, Rs.60 crore have been provisioned.
- (h) Adequate provision has been kept for establishing Incubation/Innovation centres.

19. Skill Development:

- (a) Construction of hostel blocks in different Government Polytechnic Colleges for providing better residential facilities to students will be taken during 2022-23.
- (b) Construction of workshop blocks /classrooms in different Government Industrial Training Institutes for creation of infrastructure facilities for trainees will be taken in 2022-23.

20. Sports initiatives:

- (a) Government of Jammu & Kashmir is laying main focus on sports activities for engagement of youth. Over 17 lakh youth participated in diverse sports activities and 1.26 lakh youth received coaching in different sports activities.
- (b) National Events in 17 Sports disciplines will be hosted for providing exposure to the talented athletes and interaction with the reputed players of the country.
- (c) Special programme will be initiated for involvement of mass youth in sports activities with a target of 7.50 lakh participants in different sports disciplines.
- (d) National Level competitions will be hosted in Badminton, Volleyball, Soft Tennis, Handball, Thang-Ta, Kayaking & Canoeing, Baseball and Gymnastics.
- (e) Snow & Ice based Sports Competitions through respective sports associations will be held at Gulmarg & Pahalgam.
- (f) 221 playfields/ playgrounds will be constructed in all the 20 districts.
- (g) 157, Sports court constructions/upgradation of stadiums/buildings will be taken during 2022-23.

For Youth Empowerment, Employment, Entrepreneurship, skill Development and Sports Activities, an allocation of about Rs.312.57 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2022-23 which is Rs.19.72 crore more than the previous year's budget allocation.

21. Forestry & Environment:

- (a) 1.35 crore plantations are targeted during 2022-23, out of which 26.50 lakh plants will be planted with active involvement of Village Panchayat Plantation Committees (VPPCs) to create green assets in Gram Panchayats.
- (b) Under low cost mode of greening and increasing the forest and tree cover, more than 50 lakh seeds/grass-slips are likely to be planted during the year 2022-23.
- (c) Under "One Beat Guard One Village" programme 1,500 villages will be taken up for greening of lands outside forests in 2022-23 by providing free saplings, seeds balls and grass slips to Village Panchayats for planting on village common land, kahcharai and other wastelands.
- (d) As an effort for conservation and promotion of Chinar, more than 20,000 Chinar trees will be planted in 2022-23.
- (e) A non-motorable walkway is proposed to be developed all around Wular lake which will add scenic beauty to the water body and help in preventing encroachment.

For Forest, Ecology and Environment Sector, an allocation of about Rs.200.76 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2022-23 which is Rs.9.01 crore more than the previous year's budget allocation.

22. Food Civil Supplies and Consumer Affairs:

- (a) 100% of Aadhar seeding of ration cards has been achieved, besides 99.60% Aadhar seeding at beneficiary level has been registered, which is targeted for 100% completion in 2022-23.
- (b) For better public distribution and delivery system, 100% Fair Price Shops / Government Ration Depots have been installed with 6736 Point of Sale (PoS) machines.
- (c) Construction of new stores at Chandanwadi (Anantnag), Kanil Bagh (Baramulla), and Sangal Dan (Ramban) will be taken up during 2022-23, which will strengthen the storage grid in far flung and remote areas and will enhance the storage capacity of approximately 1,000 Metric Ton.

For Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, an allocation of about Rs.306.26 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2022-23 which is Rs.3.40 crore more than the previous year's budget allocation.

23. Science and Technology:

I- Science Awareness Initiatives:

- (a) 15 Science Popularization events will be conducted in 2022-23.
- (b) Award of 150 scholarships to students at +10, +12 and Post Graduate (PG) levels will be taken up during 2022-23, besides Young Scientist Awards/Fellowships to be initiated.
- (c) Aroma cash crops will be introduced in the districts of Anantnag, Bandipora, Budgam in Kashmir division and Rajouri, Kathua and Doda in Jammu division during 2022-23.
- (d) The work on construction of Sub-Regional Science Centre, Srinagar is likely to be commenced in 2022-23.

II - New & Renewable Energy:

- (a) Under Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) Scheme, 375 number of Solar Water Pumps will be installed in 2022-23 providing electricity benefit to 47,159 souls, direct agriculture benefit to 18,750 souls and indirect agriculture benefit to 1,60,000 souls.
- (b) Under Jammu Solar City Mission, Grid tied Rooftop Solar Power Plants of aggregate capacity 200 MW in residential sector will be provided to 50,000 households in 2022-23 benefitting a population of 2 lakh souls.
- (c) Under Jammu Smart City Project, Grid tied Rooftop Solar Power Plants of aggregate capacity 12 MW will be provided to 200 number of government buildings in 2022-23 absolving hydropower sector of 48,000 KWh.
- (d) Under Srinagar Smart City Project, Grid tied Rooftop Solar Power Plants of aggregate capacity 4 MW will be provided to 70 number of government buildings in 2022-23 absolving hydropower Sector of 16,000 KWh.

For Science & Technology, an allocation of Rs.127.91 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2022-23 which is Rs.22.00 crore more than the previous year's budget allocation.

24. Financial Reforms/e-governance Initiatives:

- (a) e-Office has been implemented in Civil Secretariat including Raj Bhavan. It will be implemented in all offices of Jammu & Kashmir in 2022-23.
- (b) Online system has been created for uploading of Annual Property Returns by all the employees.
- (c) Online Annual Performance Report system in respect of all employees will be created.
- (d) E-Audit will be introduced with strengthening of Virtual Inspection Systems.

25. Security Related Activities:

- (a) 10,109 Community/Individual bunkers are being constructed in border districts.
- (b) Short-term security related works and short term basic facilities to CRPF/Jail Staff have been taken under Security Related Expenditure (SRE).
- (c) Construction of Trauma Centre at Srinagar will be initiated in 2022-23.
- (d) Adequate provision has been kept for digitization of police stations and installation of CCTVs in police stations.

26. Supplementary Grant for the current financial year 2021-22:

- (a) The original grant for the financial year 2021-22 was Rs.1,08,621 crore. During the course of year from 1st April, 2021 to 31st March, 2022 an amount of Rs.18,860.3234 crore shall be withdrawn in excess of grant under the relevant Demands out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir to defray expenses on services and purposes required during the period. This had been largely necessitated due to expenses on account of increase in salaries due to hike in Dearness Allowance (DA) and other revenue expenses including pension and other retirement benefits, World Bank aided scheme for completion of projects, increased capital allocation under Border Area Development Programme (BADP), PMGSY, NABARD loan component, PMAY-U, Tribal sub-plan, National Horticulture Mission and for meeting increased expenditure towards internal debt / ways and means advance and overdraft.
- (b) The Supplementary Jammu and Kashmir Appropriation Bill No (01) is proposed to be presented to authorize payment and appropriation of Rs.18,860.3234 crore from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the period with effect from 1st April, 2021 to 31st March, 2022.

27. BUDGET ESTIMATES OF THE FINANCIAL YEAR 2022-23 FOR THE UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR:

- (a) The total receipts for financial year 2022-23 are estimated at Rs.1,12,950 crore. Of which, Rs.1,02,322 crore are revenue receipts, Rs.10,628 crore are capital receipts and Rs.29,200 crore are Ways & Means Advances. The own revenues (both tax and non-tax) are estimated to be Rs.25,314 crore. In addition to this, Rs.35,581 crore are to flow as Central Assistance and Rs.29,750 crore under CSS/ PMDP to Union Territory of J&K.
- (b) Given these receipts, the total expenditure is estimated to be Rs.1,12,950 crore. Of this, capital expenditure will be Rs.41,335 crore and revenue expenditure to the tune of Rs.71,615 crore.

- (c) The Jammu and Kashmir Appropriation Bill No (02) is proposed to be presented to authorize payment and appropriation of Rs.1,42,150.0987 crore from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the period with effect from 1st April, 2022 to 31st March, 2023.

28. Fiscal Indicators:

- (a) The tax/GDP ratio is projected at 8.18% for 2022-23 which is higher than the previous year of 8.17%.
- (b) Debt/GDP ratio for 2022-23 is estimated at 50.84%.
- (c) GDP for the year 2022-23 has been projected at Rs.2,03,716 crore which shows a growth of 7.5% over the previous year.

- 29.** Mr. Speaker Sir, with these words, I commend the Supplementary Budget (for 01.04.2021 to 31.03.2022) and Budget for the financial year 2022-23 of the Union Territory of Jammu & Kashmir to this August House for further consideration.